mediaauditornews@gmail.com mediaauditor Epaperdainikmediaauditor.in mediaauditor वर्ष-04 अंक-184 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

सतना
04 जुलाई 2024 गुरुवार

दैनिक मीडिया ऑडीटर

दैनिक मीडियाऑडीटर

सतना, रीवा से एक साथ प्रकाशित

अफगानिस्तान की ...
@ पेज 7

संक्षिप्त समाचार

अब छपरा में भरभरा कर गिरा 10 साल पुराना ब्रिज

छपरा (एजेंसी)। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है। और इस कड़ी में बुधवार को छपरा का नाम भी जुड़ गया है, जहां जनता बाजार के ढोढनाथ मंदिर के समीप नदी पर 10 साल पहले बना पुल ध्वस्त हो गया। एकमा के पूर्व विधायक धूमल सिंह की ओर से यह पुल 10 साल पहले बनवाया गया था और आज इस पुल ने भी दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के

अनुसार 2014 के तत्कालीन विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महाचंद्र सिंह की ओर से भी इस पुल के निर्माण में विधायक निधि से सहायता दी गई थी, लेकिन आज इस पुल ने भी दम तोड़ दिया। पुल ध्वस्त होने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि यह पुल किस तरह से भरभरा कर गिर रहा है। हाल के दिनों में बिहार में कई पुल गिरने की घटनाएं सामने आई है, जिसे लेकर पूरे देश में बिहार के किरकिरी हो रही है।

घटने के बजाय चीन पर बढ़ गई हमारी निर्भरता

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीन से आयात कम करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं लेकिन इसका कुछ खास परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की पहली तिमाही में भारत की चीन और यूरोपीय संघ पर

व्यापार निर्भरता बढ़ गई है। दूसरी ओर सऊदी अरब पर हमारी निर्भरता कम हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस तिमाही में भारत की यूरोपीय संघ और चीन पर व्यापार निर्भरता क्रमशः 1 और 1.2 फीसदी बढ़ी, जबकि सऊदी अरब पर निर्भरता 0.5 फीसदी घटी। एजेंसी ने अपने ग्लोबल ट्रेड अपडेट में कहा कि वैश्विक व्यापार रुझान सकारात्मक हो गया है। यह ग्रोथ चीन, भारत और अमेरिका से निर्यात में बढ़ोतरी से प्रेरित है लेकिन यूरोप और अफ्रीका ने निराश किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 की पहली तिमाही में ग्लोबल ट्रेड में ग्रोथ रही।

मजाक समझ रखा है या! एनआईए पर भड़क गए जज

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जाली मुद्रा के मामले में एक केस की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने एनआईए से पूछा कि मामले में चार साल तक क्यों नहीं ट्रायल शुरू किया जा सका है। जस्टिस जेबी

पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कड़े शब्दों में एनआईए से पूछा कि क्या आपने इसे मजाक समझ रखा है। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि आपकी वजह से आरोपी को बिना किसी सुनवाई के चार साल तक जेल में रहना पड़ा। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई का अधिकार है।

सीएम का बड़ा ऐलान, हाथरस घटना की होगी न्यायिक जांच

जताई साजिश की आशंका, बोले, लोग मरते रहे और सेवादार भाग गए

अब तक 122 लोगों की हुई मौत, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच

लखनऊ (एजेंसी)। हाथरस की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस ने हादसे को लेकर मुख्य सेवादार और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में एक सत्संग में हुई भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने घटना में साजिश की तरफ इशारा करते हुए कहा, ''यह हादसा था या कोई साजिश और अगर साजिश थी तो इसमें किसका हाथ है। इन सभी पहलुओं को जानने के लिए हम न्यायिक जांच भी कराएंगे जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में की जाएगी।'' यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हुई है। 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और

आगरा में रातभर शवों का पोस्टमॉर्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर-उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौत की पुष्टि की है। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। बुधवार सुबह साढ़े 11 बजे सीएम योगी भी हाथरस पहुंच गए। जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। घटनास्थल गए। अफसरों से पूरे हादसे की जानकारी ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- यह हादसा साजिश जैसा है। लोग मरते गए। सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने न तो प्रशासन को सूचना दी और न ही मदद की और ली। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। हमने भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए, लेकिन ऐसी चीजें नहीं आई।

सुनीता विलियस के पहुंचते ही बढ़ी स्पेस स्टेशन की मुश्किल!

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की वापसी अभी नहीं हो पाई है। इनके स्पेसक्राफ्ट में हीलियम रिसाव और थ्रस्टर में खराबी देखी गई थी लेकिन अच्छी बात ये रही कि उनका अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ गया। सुनीता विलियम्स के स्पेस में फंसने की चर्चा है। नासा का कहना है कि वह फंसी नहीं हैं लेकिन हाल ही में अंतरिक्ष में एक हादसा देखने को मिला था, जिससे आईएसएस में मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्रियों की जान पर बन आई। इन्हें स्पेस स्टेशन में ही शेल्टर लेना पड़ा। दरअसल रूस की एक खराब सैटेलाइट स्पेस में फट गई थी, जिसका मलबा आईएसएस के लिए भी खतरा बन गया था।

झारखंड में हेमंत सोरेन फिर बनेंगे मुख्यमंत्री

चंपाई सोरेन होंगे समन्वय समिति के चेयरमैन!

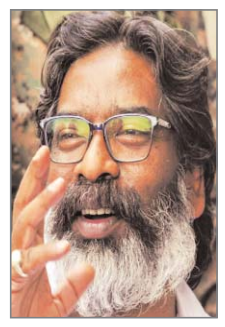

रांची (एजेंसी)। झारखंड में तेजी से बनते-बिगड़ते सियासी समीकरण के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इंडिया अलायंस विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में उपस्थित गठबंधन के सभी विधायकों ने एक मत से हेमंत सोरेन को अपना नेता चुना। इससे पहले बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पहले अपने इस्तीफे की पेशकश। उसके बाद चंपाई सोरेन ने ही विधायक दल के नेता और राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया है। वहीं चंपाई सोरेन समन्वय समिति के चेयरमैन होंगे। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से इंडिया अलायंस की ओर से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। हेमंत सोरेन को फिर से विधायक दल का नेता चुने जाने के निर्णय के बाद सीएम चंपाई बैठक से बाहर निकल गए।

निशिकांत दुबे बोले-चंपाई सोरेन युग समाप्त

इधर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि चंपाई सोरेन युग अब समाप्त हो गया है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि परिवारवादी पार्टी में परिवार के बाहर के लोगों का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। काश, आंदोलनकारी मुख्यमंत्री बिरसा भगवान से प्रेरित होकर भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़े हो पाते।

राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच, विपक्ष का वॉकआउट

पीएम बोले-पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, मणिपुर की स्थिति हो रही सामान्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। 1 घंटा 50 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री ने नीट, मणिपुर संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार, नीट-यूजी, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जम्मू-कश्मीर, इंदिरा, राहुल, दलितों पर बोले। प्रधानमंत्री जब 32 मिनट बोल चुके थे, तब विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। वॉकआउट प्रधानमंत्री द्वारा सोनिया गांधी पर निशाना साधने के बाद हुआ। उन्होंने कहा- ये लोग ऐसे हैं, जो ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी हैं। वे काम करने में विश्वास नहीं रखते, वे बस इंतजार करना जानते हैं। इस पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बोले- ये लोग मुझे नहीं, संविधान को पीठ दिखा रहे हैं। पीएम ने कहा- कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, इसलिए वे मैदान छोड़कर भाग गए। नारे लगाना, चिल्लाना और भाग जाना, यही उनकी नियति है। पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। मेरी इच्छा थी, सारे दल इस पर अपनी राय रखते। लेकिन यह मुद्दा भी इन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दी। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है। इन्हें सख्त सजा मिले, इसलिए एक के बाद एक ऐक्शन लिए जा रहे हैं। हमने इसके लिए सख्त कानून बनाया है। मणिपुर में लगातार हिंसक घटनाएं कम हो रही हैं। स्कूल कॉलेज दफ्तर और अन्य संस्थान चल रहे हैं। मणिपुर में भी परीक्षाएं हुई हैं। जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डाल रहे हैं, कार्रवाई होगी।

टीम इंडिया से आज सुबह मुलाकात करेंगे पीएम मोदी

13 साल बाद विश्व विजेता बना है भारत, लौट रही है टीम

नई दिल्ली (एजेंसी)। बारबाडोस से लौटने के बाद टी-20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 4 जुलाई को सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे। तूफान बेरिल के कारण टीम इंडिया पिछले दो दिनों से बारबाडोस में फंसी हुई थी। टीम इंडिया 4 जुलाई को भारत वापस आ रही है। टीम मंगलवार को बारबाडोस से रवाना होगी और बुधवार को दिल्ली पहुंचेगी। टी20 विश्व चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम मंगलवार शाम को चार्टर विमान से स्वदेश रवाना होगी।

बारबडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यहां हवाई अड्डा 'अगले छह से 12 घंटों' में चालू हो जाएगा जिसे श्रेणी चार के तूफान के कारण बंद किया गया था। रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम, उसका सहयोगी स्टाफ, भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के कुछ अधिकारी और खिलाड़ियों के परिवार तूफान बेरिल के कारण पिछले दो दिन से यहां फंसे हुए हैं। टीम ने शनिवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर खिताब जीता। खिलाड़ियों को बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

एमवीए को हराने के लिए पुराने फॉर्मूले पर लौट आई बीजेपी

- महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों में सामने आई सोशल इंजीनियरिंग
- पंकजा मुंडे के साथ कई अन्य पूर्व ओबीसी नेताओं पर खेला 'दांव'

मुंबई (एजेंसी)। लोकसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में अपने पुराने फॉर्मूले पर लौट रही है। पार्टी ने राज्य में दिग्गज ओबीसी नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा के साथ जिन चार अन्य कैंडीडेट को विधान परिषद चुनावों में उतारा है। उसमें मा-ध-व (माली-धनगर, वंजारी) फॉर्मूला निकलकर आया है। इसे बीजेपी की तरफ से फिर अपने कोर ओबीसी वोट

बैंक को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने टिकटों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी से दलित के साथ ओबीसी वोट भी बीजेपी से छिटके थे। इसका खामियाजा यह हुआ कि राज्य में को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और वह 23 से गिरकर नौ सीटों पर आ गई। विधान परिषद के कैंडीडेट का ऐलान होने के बाद बीजेपी अपने कोर वोट बैंक की तरफ लौट रही है।

इस बार जगन्नाथ रथयात्रा 2 दिन की, अबकी रहेगी जबरदस्त धूम

7 जुलाई की शाम को शुरू होगी यात्रा, 8 को गुंडिचा मंदिर पहुंचेंगे रथ, 1971 में भी ऐसा हुआ था

पुरी (एजेंसी)। इस साल पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथयात्रा दो दिन चलेगी। जगन्नाथ मंदिर का पंचांग बनाने वाले ज्योतिषी का कहना है कि इस साल आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में तिथियां घट गई। जिसके चलते रथयात्रा से पहले होने वाली पूजा परंपराएं 7 जुलाई की शाम तक चलेंगी। रथयात्रा की तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए सुबह शुरू होने वाली रथयात्रा शाम को शुरू होगी। इससे पहले 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। ज्योतिषी डॉ. ज्योति प्रसाद का कहना है, 7 जुलाई को दिनभर पूजा परंपराएं चलेंगी और शाम को 4 बजे के आसपास रथयात्रा शुरू होने की संभावना है। सूर्यास्त के बाद रथ नहीं हांके जाते हैं, इसलिए रथ रास्ते में ही रोके दिए जाएंगे। 8 को सुबह जल्दी रथ चलना शुरू होंगे और इसी दिन गुंडिचा मंदिर पहुंच जाएंगे। हर साल जेठ महीने की पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाया जाता है। इसके बाद वो बीमार हो जाते हैं और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते। 16वें दिन भगवान का श्रृंगार किया जाता है और नवयौवन के दर्शन होते हैं। इस बार तिथियों की गड़बड़ी के चलते ये पखवाड़ा 15 की बजाय 13 दिन का ही रहा। इसी कारण भगवान के ठीक होने का दिन रथयात्रा वाली तिथि को पड़ रहा है।

जम्मू-कश्मीर में सेना ने बस खाई में गिरने से बचाई

- ब्रेक फेल हुआ, लोग कूदने लगे; जवानों ने पहियों के नीचे पत्थर रखकर रोकी

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में एनएच-44 पर भारतीय सेना की सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। यहां मंगलवार को अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस का ब्रेक फेल हो गया। हाईवे के किनारे गहरी खाई थी। बस में 45 लोग सवार थे, जो अमरनाथ से पंजाब लौट रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बनिहाल के पास नचलाना पहुंचने पर ड्राइवर को ब्रेक फेल होने का पता चला। बस काफी स्पीड में थी। ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया था, जिससे गाड़ी तेजी से खाई की तरफ बढ़ने लगी। इससे बस में सवार यात्री दहशत में आ गए। जान बचाने के लिए यात्री चलती बस से कूदने लगे। इसी दौरान सेना और पुलिस के जवानों ने बस की स्पीड को कम करने की कोशिश की। उन्होंने बस के पहियों के नीचे पत्थर रख दिए। इससे बस रुक गई और खाई में गिरने से बच गई। इस तरह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पूर्वोत्तर में 'बारिश ही बारिश', बद्तर हुए हालात

● असम में बाढ़ से तीन लोगों की मौत, 11 लाख लोग प्रभावित ● मणिपुर में स्कूल-सरकारी दतर बंद, भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। मानसून ने तय समय से 6 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया है। देशभर के तकरीबन सभी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। नॉर्थ-ईस्ट में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। मणिपुर और असम में बाढ़ आ गई है। मणिपुर सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा की है, जबकि स्कूल 4 जुलाई तक बंद रहेंगे। मंगलवार को सेनापति नदी में गिरे 25 साल एक व्यक्ति का शव निकाला गया। भारत-म्यांमार सड़क के 3 किमी से अधिक हिस्से में भी बाढ़ आ गई है। 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम में भी तीन लोगों की बाढ़ से जान चली गई। इससे राज्य

में इस साल बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। राज्य के 23 जिलों में 11.3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सोमवार तक 19 जिलों में 6.44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित थे। गुजरात के जूनागढ़ में सड़कें बारिश के पानी में डूब गई हैं। इसकी वजह से 30 गांवों का संपर्क कट गया है। वंथली में सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक रिकॉर्ड 361 मिमी बारिश हुई। सौराष्ट्र और दक्षिणी क्षेत्र में 200 मिमी से ज्यादा बारिश हुई। अहमदाबाद में दो मंजिला बिल्डिंग की सीढ़ियों का एक हिस्सा ढह गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने बिल्डिंग में फंसे 16 लोगों को निकाला।

संक्षिप्त समाचार

प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है बजट-ऊर्जा मंत्री तोमर

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा आज विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किया गया। बजट प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाये गये इस बजट में युवाओं, किसानों और गरीबों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऊर्जा विभाग के लिए इस वर्ष 19 हजार 406 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में एक हजार 46 करोड़ रूपये अधिक है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को निर्वाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। श्री तोमर ने बताया कि अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3500 करोड़ रूपये और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 6290 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। आर.डी.एस.एस. योजना के लिए 3150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 565 करोड़ रूपये एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 5 एच.पी. पंपों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क बिजली देने के लिए 2475 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

मातृ-शक्ति को संबल और सम्मान प्रदान करने वाला है बजट

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि उप-मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा आज प्रस्तुत बजट मातृ-शक्ति को संबल और सम्मान प्रदान करने वाला बजट है। यह सबका साथ सबका विकास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, महिला, युवा एवं किसान सहित सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि सबसे प्रचलित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए वर्ष 2024-25 में 18 हजार 984 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए 3 हजार 469 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1231 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। महिला-बाल विकास विभाग के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 26 हजार 560 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 81 प्रतिशत अधिक है।

संस्कृति, पर्यटन, सभ्यता और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने वाला बजट

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्याय और धर्मस्व मंत्री श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने कहा कि आज उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट संस्कृति, पर्यटन, सभ्यता, सरोकार और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने वाला बजट है। मंत्री श्री लोधी ने कहा कि यह बजट युवाओं, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, सामाजिक उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना का विस्तार और औद्योगिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में पर्यटकों की सुविधाओं के ?लिये 666 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग सौ करोड़ अधिक है। प्रदेश के सांस्कृतिक उत्थान के लिये वर्ष 2024-25 में एक हजार 81 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिये वर्ष 2024-25 में 50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

गरीब, किसान, मजदूर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला बजट

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि प्रदेश सरकार का वर्ष 2024-25 का बजट प्रदेश में विकास तथा जनता के जीवन में सहजता लाने वाला, जन-हितैषी बजट है। युवा व महिला सशक्तिकरण के साथ प्रदेश की सुदृढ़ अधोसंरचना, किसान, गरीब, मजबूर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला बजट है। गरीब परिवार की बेटियों के सम्मानपूर्वक विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना राशि में तीन गुना वृद्धि कर 225 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में भी 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए 4 हजार 421 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान करना इस वर्ग के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। कृषि के साथ उद्यानिकी को भी बढ़ावा देकर राज्य सरकार कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत-संकल्पित है। किसानों को उन्नत किस्म के बीज और पौधे मुहैया कराने के लिए बजट में पौधशाला विकास के लिए 151 करोड़ तथा खाद्य प्र-संस्करण विकास के लिये 124 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा और संस्थान के संस्कारों को हमेशा याद रखें विद्यार्थी-मंगुभाई पटेल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि शिक्षा को ज्ञान आधारित बनाने के साथ सेवा, संस्कार और संवेदनशीलता के मूल्य केन्द्रित बनाना होगा। विद्यार्थी शिक्षा और संस्थान के संस्कारों को हमेशा याद रखें। माता-पिता के संघर्षों को नहीं भूलें और उनके योगदान का सम्मान करें और कृतज्ञ रहें। श्री पटेल आई.ई.एस. ग्रुप के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित जनों और विद्यार्थियों को एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ने की अपील भी की। इस अवसर पर कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल मौजूद थे। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में समर्थ, सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि

शिक्षा के व्यावसायिक और व्यावहारिक पक्षों में समन्वय जरूरी है। संस्थान को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप भावी पीढ़ी को तैयार करना होगा। इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों को प्रभावी रूप से लागू करना होगा। उन्होंने संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा खेलकूद, स्वरोजगार, प्रबंधन, आदि क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त उपलब्धियों की सराहना और संस्थान के 25 वर्ष के समुचित नेतृत्व और प्रबंधन को बधाई दी। रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री श्री गौतम टेटवाल ने और मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाने संस्थान के प्रयासों की सराहना की।

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष डॉ भरत सिंह शरण ने विकसित भारत की संकल्पनाओं को साकार करने के लिए संस्थान के सहयोग, सक्रियता और प्रतिबद्धता को निरंतर जारी रखने की बात कही। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलन कर किया। श्री पटेल का आई.ई.एस. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इंजी. श्री बी.एस. यादव ने पुष्पगुच्छ से स्वागत और शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। राज्यपाल श्री पटेल ने रजत जयंती के अवसर पर संस्थान को 25 पौधे रोपण के लिए भेंट किए। उन्होंने समारोह में मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया। स्वागत भाषण कुलाधिपति इंजी. श्री बी.एस. यादव ने दिया और आभार आई.ई.एस. ग्रुप के सी.ई.ओ. श्री देवांश सिंह ने किया।

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार, एक लाख 42 हजार 565 रुपये हुई प्रति व्यक्ति आय

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय चार गुना बढ़ी है। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक लाख 42 हजार 565 रुपये हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना (1,32, 010) में प्रति व्यक्ति आय में 10 हजार 55 रुपये की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद स्थिर भावों पर भी प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 38 हजार 497 से बढ़कर 66 हजार 441 रुपये हो गई है। सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में कृषि उत्पादकता में सकारात्मक रुझान, औद्योगिक स्थिरता और सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। वहीं, प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) भी बढ़कर 13 लाख 63 हजार 327 करोड़ हो गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की जीएसडीपी 12 लाख 46 हजार 471 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 9.37 प्रतिशत की वृद्धि कृषि, उद्योग और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुई है। यह आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण के हैं, जो प्रदेश सरकार द्वारा बजट से एक दिन पूर्व मंगलवार को जारी किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के लिए स्थित भावों पर जीएसडीपी छह लाख 60 हजार 363 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वर्ष से छह लाख 22 हजार 908 करोड़ रुपये से अधिक है। यानी इसमें लगभग 6.01 प्रतिशत वास्तविक वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था न केवल बढ़ रही है बल्कि उत्पादन और सेवाओं में वास्तविक लाभ भी प्राप्त कर रही है। कृषि में उन्नति, औद्योगिक विकास और विशेष रूप से आइटी व पर्यटन में बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र सामूहिक रूप से राज्य के आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रहा है।

कार और एसी का इतेमाल ना करने वाले बुजुर्गों को करा रहे हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। नगर की एक प्रमुख सामाजिक संस्था श्री गुजराती समाज ने अपने समाज के बुजुर्ग सदस्यों को हवाई जहाज से मुफ्त तीर्थयात्रा कराने की पहल की है। यह संस्था बुजुर्गों को अयोध्या, प्रयागराज एवं काशी विश्वनाथ की हवाई यात्रा करा रही है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था मंगलवार को रवाना हुआ। बुधवार को तीर्थ यात्रियों का दूसरा दल रवाना होगा। यह तीर्थ यात्रा उन बुजुर्गों के लिए बिल्कुल निशुल्क है, जो कार एवं एसी का इस्तेमाल नहीं करते। शेष तीर्थ यात्रियों को भी सिर्फ 50 प्रतिशत शुल्क ही देना होगा। श्री गुजराती समाज के अध्यक्ष संजय पटेल

ने बताया कि यात्रा दो से छह जुलाई तक चलेगी। दो जुलाई को रवाना हुए तीर्थ यात्री पांच जुलाई को वापस लौट आएंगे, जबकि बुधवार को तीर्थ के लिए रवाना होने वाले बुजुर्ग छह जुलाई को राजधानी वापस लौटेंगे। कार्य कारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार समाज के ऐसे सदस्य जो कार एवं एसी का उपभोग नही करते हैं, साथ ही पहली बार हवाई यात्रा करेंगे। ऐसे नौ परिवार के सदस्यों को समाज निशुल्क हवाई यात्रा करवा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ सदस्यों का 50 प्रतिशत खर्च समाज वहन कर रहा है। इस तीर्थयात्रा में समाज के 37 पुरुष एवं 33 महिलाए शामिल हैं।

आधार के लिए नामांकन के बाद कार्ड मिलने में लग सकते हैं छह माह, तीन स्तर पर होगा सत्यापन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। अब यदि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति के द्वारा आधार के लिए नामांकन कराया जाता है तो उन्हें कार्ड मिलने में छह माह तक का वक्त लग सकता है। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने आयु समूह के आधार नामांकन के लिए बड़ा बदलाव किया है। इस कारण आधार कार्ड मिलने की अधिकतम समयसीमा अब छह महीने तय कर दी गई है। नई प्रक्रिया के तहत आधार नामांकन के बाद इनका राष्ट्रीय, राज्य और जिला यानी स्थानीय स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। यानी अब तीन स्तरीय सत्यापन व्यवस्था लागू की गई है। जिस आधार सेवा केंद्र से ऐसे लोग नामांकन कराएंगे, उस केंद्र से पहले इनका डाटा यूआइडीएआइ के डाटा सेंटर बेंगलुरु पहुंचेगा। वहां से सत्यापन के लिए इसे राजधानी भेजा जाएगा। इसके बाद राजधानी से संबंधित जिले में भेजा जाएगा। इन तीन स्तरों पर सत्यापन के बाद ही संबंधित व्यक्ति को आधार कार्ड मिल सकेगा। राज्य स्तर और जिला स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक दस वर्ष पहले के आधार कार्ड वाले लोगों के लिए पता और पहचान नवीनीकरण करवाना इसीलिए आवश्यक किया गया है। इसके तहत आनलाइन और आफलाइन दोनों मोड से व्यवस्था की गई है। आनलाइन फ्री नवीनीकरण की डेडलाइन भी तीन बार बढ़ाई जा चुकी है। पिछले महीने यह डेडलाइन 14 जून से 14 सितंबर तय की गई। आनलाइन नवीनीकरण में पता और पहचान दोनों से जुड़े दस्तावेज अपलोड करना भी अनिवार्य हैं। इसके बिना नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। आफलाइन नवीनीकरण में बायोमेट्रिक डाटा (फिंगर प्रिंट, आइरिश स्कैन या फेस आथेंटिकेशन) भी किया जा रहा है। सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं को देखते हुए नई व्यवस्था की गई है। आधार योजना के पहले चरण में 2010-11 में नामांकरण के बाद जिन लोगों ने आधार बनवाए थे, तब निजी एजेंसियों के पास भी आधार बनाने का जिम्मा था। तब आवेदक द्वारा दी गई मौखिक जानकारी के आधार पर ही नामांकन कर लिए गए थे। इनमें से कुछ आधार फर्जी होना पाया गया था। भोपाल में ही पांच वर्ष पहले फर्जी आधार के लगभग 17 मामले सामने आए थे।

मंत्री श्री काश्यप ने क्लस्टर विकास के अभिन्यास की अनुमति प्रदान की

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य काश्यप ने नीमच जिले की मनासा तहसील के ग्राम दुधवा के 15 हेक्टर क्षेत्र में क्लस्टर विकास के अभिन्यास की अनुमति प्रदान की है। यह अनुमति एस.पी.व्ही. महेश इंडस्ट्रियल डेवलपर्स मनासा को दी गई है। इस अवसर पर एमएसएमई विभाग के सचिव श्री नवनीत मोहन कोठारी, एस.पी.व्ही. के सदस्य श्री आशीष काबरा निम्बा हेड, श्री ज्वाला प्रसाद राठी मनासा एवं श्री विनय प्रकाश काबरा निम्बा हेड उपस्थित थे। मंत्री श्री काश्यप ने एस.पी.व्ही. के सदस्यों को अधोसंरचना निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर उद्योग लगाने के लिये प्रेरित किया। श्री काश्यप ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि जो भी कठिनाई होगी उसका त्वरित समाधान किया जाएगा। मध्यप्रदेश में औद्योगिकीकरण के विकास के हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के सपने को साकार करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।

बाल आयोग ने बालिका गृह का निरीक्षण किया, माना सुरक्षा व्यवस्था में हुई थी चूक

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। नेहरू नगर स्थित बालिका गृह से खिड़की की जाली तोड़कर गायब हुई चार नाबालिग बालिकाओं के मामले को लेकर मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने मंगलवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद आयोग ने माना कि बालिका गृह में सुरक्षा व्यवस्था की कमी है। दो महिला पुलिस आरक्षक तैनात होने चाहिए, लेकिन घटना के दिन एक भी नहीं थी।सिर्फ एक चौकीदार था।

यहां तक कि बालिका गृह में अधीक्षिका आकांक्षा तोमर भी उपस्थित नहीं थी।आयोग ने जांच प्रतिवेदन में लिखा है कि बालिका गृह में पुलिस आरक्षकों की तैनाती की जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को तगड़ी की जाए।आयोग के सदस्य अनुराग

पांडेय, निवेदिता शर्मा,ओंकार सिंह,डा. निशा श्रीवास्तव की टीम ने निरीक्षण किया और वहां उपस्थित बालिकाओं से बातचीत की। बालिकाओं का कहना है कि वे कूलर की आवाज के कारण खिड़की तोड़ने की आवाज सुन नहीं पाईं।आयोग ने बालिका गृह में व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। जहां पर 16 बालिकाएं पाईं गईं।साथ ही वहां के शौचालय के गेट टूटे हुए थे, जिसे ठीक करने की अनुशंसा की। साथ ही जिस दीवार को फांदकर बालिकाएं भागी हैं,उसकी दीवार को ऊंचा करने के लिए भी कहा है। मामले में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घटना सोमवार तड़के करीब पांच बजे की बताई गई है। प्रार्थना के समय गिनती करने पर जब चार बालिकाओं की संख्या कम निकलीं तो उनकी तलाश शुरू की गई।आसपास तलाश करने के बाद भी जब उनका कुछ पता नहीं चल पाया तो प्रबंधन ने थाने जाकर चारों शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से उनकी तलाश कर रही है। इधर, बालिक गृह के प्रबंधन की जिम्मेदारी महिला बाल विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में गोलमोल जवाब देकर मामले से किनारा कर रहे हैं। कमला नगर थाने की टीआई निरूपा पांडेय के अनुसार इलाके में लगे सीसीटीवी खंगालने पर चारों बालिकाएं सीधे रास्ते में चलने के बजाए घूम-फिरकर जाते हुए दिखाई दी हैं।

55,709 करोड़ रुपये रहा मप्र का राजकोषीय घाटा, कुल जीएसडीपी का 4.02 प्रतिशत

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश का 55,709 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा रहा है। यह अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4.02 प्रतिशत है। वर्ष 2023-24 में राजस्व आधिक्य राशि 413 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, इसे कोरोना काल की राजस्व घाटे की स्थिति से उबरने एवं एक स्थिर और मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत मान सकते हैं। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य करों का हिस्सा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 6.16 प्रतिशत से बढ़कर 6.20 प्रतिशत हो गया है इस अवधि के दौरान राज्य के अपने कर संग्रह में 12.79 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ोतरी हुई। भूमि राजस्व 1,200 करोड़ रुपये, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क 10,400 करोड़ रुपये, और एसजीएसटी 32,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। कुल राजस्व प्राप्तियां 2,25,710 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो कुल प्राप्तियों का 80.14 प्रतिशत है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय, वर्ष 2019-2020 में 3.23 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-2023 में 3.48 प्रतिशत होने और वर्ष 2023-2024 में बढ़कर 3.90 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान ऋण और अग्रिम भी 0.11 प्रतिशत से बढ़कर 0.16 प्रतिशत होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग की सुविधाओं से लाभान्वित किया है। सरकार द्वारा बैंकिंग सेवाओं को सुलभ एवं कृषि, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों के लिए ऋण विस्तार के प्रयास किए जा रहे, फलस्वरूप 2005-06 से 2023-24 तक कृषि ऋण में 16.4 प्रतिशत सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) की वृद्धि एवं एमएसएमई क्षेत्र में 33.85 प्रतिशत सीएजीआर की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गैर-(एनपी.ए) में क्रमशः 47,19 एवं 6 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। दलहन के उत्पादन में 42.62 प्रतिशत की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश ने प्रमुख फसलों के उत्पादन में 0.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। हालांकि अनाज के उत्पादन में 1.91 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि दलहन में 42.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और तिलहन में 7.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मसालों का उत्पादन 2022-23 में 52.62 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 53.59 लाख मीट्रिक टन हो गया। सब्जियों का उत्पादन 236.41 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 242.62 लाख मीट्रिक टन हो गया, और फलों का उत्पादन 95.10 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 95.54 लाख मीट्रिक टन हो गया। आयुष्मान कार्ड जारी करने और पथ विक्रेताओं को ऋण देने में देश में मप्र प्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रदेश में 9.50 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 7.50 लाख आवास पूरे हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री कॉलेज आफएक्सीलेंस में तीन दिवसीय दीक्षारंभ समारोह संपन्न

प्रधानमंत्री कॉलेज आफएक्सीलेंस की गरिमा के अनुरूप महाविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण बनाए: प्राचार्य डॉ सिंह

मीडिया ऑडीटर, सीधी निप्र। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार सत्र 2024-25 के नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम अंतर्गत तीन दिवसीय दीक्षारंभ समारोह का आयोजन प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई को अपर कलेक्टर श्री राजेश शाही के मुख्य अतिथ्य एवं महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में हुआ। प्रथम दिवस नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं को नई शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, महाविद्यालय की गतिविधियों, विभिन्न विभागों और संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

द्वितीय दिवस का कार्यक्रम प्रात: 9 बजे महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में 75 प्रतिशत उपस्थिति के संदर्भ में डॉ. आर.बी.एस. चौहान ने जानकारी दी, सीसीई के संदर्भ में डॉ. उमाकांत साहू, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल के संदर्भ में डॉ. गुलशेर अहमद और छात्रवृत्ति की वृहद विवेचना डॉ विनोद प्रजापति ने की। छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय के सभी विभागों का भ्रमण कराया गया जहां शैक्षणिक स्टाफ एवं विभागों की गतिविधियों से उनका परिचय हुआ। डॉ. अरविंद कुमार त्रिपाठी ने प्रोजेक्टर के संदर्भ में छात्र-छात्राओं को जानकारी दी, कैरियर मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट से संबंधित जानकारी डॉ विनोद कुमार साकेत ने दी जबकि इनक्यूबेशन सेंटर संबंधी जानकारी डॉ. राकेश कुमार प्रजापति ने दी। एनसीसी की संपूर्ण जानकारी प्रभारी डॉ. उमाकांत साहू, एनएसएस की जानकारी प्रभारी डॉ सिद्धार्थ कुमार वर्मा ने दी।

तृतीय दिवस में संवेदीकरण, जागरूकता एवं नशा मुक्ति एवं सूचना का अधिकार तथा छात्रावास के संबंध में प्रभारी अधिकारी डॉ. राम सुरेश भारती ने छात्र-छात्राओं को परिचित कराया। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संदर्भ में डॉ. अरुणा ठाकुर, डॉ. गुलशेर अहमद ने साइबर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में जानकारी प्रदान की। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रारंभ होने वाली बस सेवा के प्रभारी अधिकारी एवं भूगोल विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉ. के.एस. नेताम और उनके सहयोगी डॉ. राकेश कुमार प्रजापति ने जानकारी प्रदान की। समूह निर्माण अभ्यास, समूह का महत्व, एकता का महत्व एवं खेल गतिविधियों के संदर्भ में डॉ. रविंद्रनाथ सिंह ने विस्तृत जानकारी प्रदान की। पूर्व छात्रों से परिचय कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और एलुमिनाई के संदर्भ में प्रभारी अधिकारी डॉ. उमेश कुमार विश्वकर्मा ने जानकारी प्रदान की, जबकि महाविद्यालय में बच्चों के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए डॉ. आरबीएस चौहान ने अनुसंधान क्या है,अनुसंधान की परिकल्पना क्या है और अनुसंधान के उद्देश्य क्या है आदि के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम के अंतिम सत्र में छात्र-छात्राओं से प्रश्न उत्तर के माध्यम से उनके विचार आमंत्रित किए गए: समापन समारोह के पूर्व नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें अनेक छात्र-छात्राओं ने लोकगीत, कहानी, चुटकुले एवं लोक कला पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पी के सिंह ने नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए परिसर को साफ सुथरा रखने, कक्षाओं में उपस्थित रहने तथा महाविद्यालय में संचालित हो रहे नवीन पाठ्यक्रमों इत्यादि की जानकारी देते हुए प्राध्यापकों से भी अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस की गरिमा के अनुरूप महाविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण बनाए। त्रि दिवसीय कार्यक्रम के संबंध में डॉ. आरबीएस चौहान ने आभार प्रदर्शन किया तथा छात्र-छात्राओं को प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस का छात्र बनने की बधाई दी।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनिल कुमार सिंह, डॉ. आशुतोष पांडे, डॉ. कोमल पांडे, डॉ. रितु साहू एवं डॉ. विभा कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त सीनियर प्राध्यापक डॉ. के एस नेताम, डॉ प्रभाकर सिंह, डॉ. अनिल कुमार सिंह, डॉ. अरुणा ठाकुर, डॉ. आरएन स्वर्णकार, डॉ. अरविंद त्रिपाठी, डॉ. संतोष सिंह चौहान, डॉ. एके शर्मा एवं महाविद्यालय के समस्त सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

शासकीय महाविद्यालय मड़वास में दीक्षारम्भ कार्यक्रम सम्पन्न

मीडिया ऑडीटर, सीधी निप्र। शासकीय महाविद्यालय मड़वास में तीन दिवसीय दीक्षारम्भ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। दीक्षारम्भ कार्यक्रम के तृतीय दिवस में संवेदीकरण और जागरुकता के बारे में डॉ. लक्ष्मीकांत ने जानकारी दी वही सूचना अधिकार अधिनियम 2005 और लोकसेवा गारंटी अधिनियम की जानकारी डॉ. अनुराग तिवारी ने दी। स्वास्थ्य सुरक्षा परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य के सम्बंध में ममता कुशवाहा ए.एन.एम और प्रदीप पाण्डेय एस.टी.एस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़वास ने जानकारी दी।

दीक्षारम्भ के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पवन मिश्रा जनभागीदारी अध्यक्ष शासकीय महाविद्यालय मझौली उपस्थित थे तो विशिष्ट अतिथि के रूप में रामदयाल कोल सरपंच ग्राम पंचायत दादर उपस्थित थे। इस अवसर पर पवन मिश्रा ने सभी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना दी। कार्यक्रम का संचालन डॉ राजेश पटेल ने किया वही आभार डॉ. संगीता मिश्रा ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के डॉ. दीपक अग्निहोत्री, डॉ. अनुराग तिवारी, डॉ. कमलेश जायसवाल, डॉ. पंकज मिश्रा, डॉ. लक्ष्मीकांत कुशवाहा, डॉ. अमिता खरे, डॉ. निशा सिंह, डॉ. सौरभी गुप्ता, डॉ. ज्योति रजक, डॉ. संगीता मिश्रा, डॉ सुरेंद्र गुप्ता, प्रवीण साकेत, दीपराज प्रजापति, सुंदरलाल प्रजापति, अनिल केवट सहित नवप्रवेशित छात्र/छात्राएं एवं पूर्व छात्र छात्राएं उपस्थित थे।

शून्य शक्ति अभियान में 1588 सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत

मीडिया ऑडीटर, सीधी निप्र। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी की पहल पर सभी पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले में शून्य शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गत एक माह में अभी तक 1588 सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत किये गये हैं। विकासखंड कुसमी में 72, मझौली में 240, रामपुर नैकिन में 415, सीधी में 483 एवं सिहावल में 378 सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत किए गए हैं।

कलेक्टर श्री सोमवंशी ने बताया कि केंद्र सरकार एवं राज्य शासन द्वारा वृद्ध, दिव्यांग एवं कल्याणी महिलाओं की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने के उद्देश्य से शून्य शक्ति अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामवार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जहाँ चिन्हित पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर उन्हें पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि ऐसे पात्र हितग्राही जिनका बीपीएल में नाम नहीं होने के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाई है, उनके पात्रतानुसार बीपीएल में नाम जोड़ने की कार्यवाही भी की जा रही है। कलेक्टर ने ऐसे सभी हितग्राहियों को लोकसेवा केंद्र के माध्यम से बीपीएल में नाम जोड़ने का आवेदन करने के लिए कहा है।

कलेक्टर ने बताया कि पोर्टल के अनुसार जिले में वर्तमान में 18827 हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए संभावित पात्रों की सूची में प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए उन्हें लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया है कि पूरी संवेदनशीलता के साथ इस अभियान का क्रियान्वयन किया जाए जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति हितलाभ से वंचित नहीं रहे। कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी ग्रामपंचायतों से इस आशय के प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाएंगे कि आज दिनांक की स्थिति में कोई भी पात्र हितग्राही योजना के हितलाभ से वंचित नहीं है।

मझौली में नैनो उर्वरक के उपयोग के संबंध में संगोष्ठी आयोजित

मीडिया ऑडीटर, सीधी निप्र। म.प्र. डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला सीधी एवं इफ्को के संयुक्त तत्वाधान में मां काली सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र विकासखंड मझौली में नैनो उर्वरक उपयोग के संबंध एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें इफ्को के जनरल मैनेजर प्रकाश चंद पाटीदार एवं जिला प्रबंधक इफ्को राजेश मिश्रा द्वारा नैनो उर्वरक जैसे नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी, संगरिका आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही 16 नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के डिब्बे तथा सभी कृषि सखियों को एक-एक बैग भी इफ्को से दिए गए। कृषि सखियों से अपेक्षा की गई कि जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों को बताएंगी ताकि यूरिया और डीएपी की जगह पर नैनो यूरियाऔर नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

संगोष्ठी में जिला पंचायत सदस्य कृष्ण लाल पयासी, एसडीएम मझौली आर पी त्रिपाठी, विधायक प्रतिनिधि प्रवीण तिवारी, समृद्ध किसान आकाश सिंह, विकासखंड प्रबंधक चंद्रकांत सिंह बघेल एवं समस्त विकासखंड टीम सहित म.प्र. डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षित कुल 65 कृषि सखियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

विकास खण्ड कुसमी में शिक्षा विभाग की खण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन

गुणवत्तायुक्त, सर्वोन्मुखी शिक्षा प्रदान कर बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास करने पर जोर दिया गया

मीडिया ऑडीटर, सीधी निप्र। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के मार्गदर्शन में सीएम राइज विद्यालय कुसमी के सभागार में 03 जुलाई को सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डॉ. डी के द्विवेदी तथा जिला शिक्षा केंद्र के सहायक परियोजना समन्वयक अकादमिक विष्णु पाण्डेय, सहायक परियोजना समन्वयक आईईडी रजनीश श्रीवास्तव एवं सहायक यंत्री सत्य प्रकाश शुक्ला सर्व शिक्षा अभियान एवं अंगिरा प्रसाद द्विवेदी बीआरसीसी कुसमी द्वारा कुसमी विकास खण्ड के समस्त प्राचार्य, जन शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा मानीटरिंग अमले के साथ खण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में गुणवत्तायुक्त, सर्वोन्मुखी शिक्षा प्रदान कर बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास करने पर जोर दिया गया। साथ ही नामांकन (प्रवेश), कक्षोंन्नति, मैपिंग, पुस्तक रिसीविंग एवं वितरण तथा गणवेश वितरण की समीक्षा की गई। प्रशस्त एप में छात्रों का पंजीयन, एनआईएलपी एप में असाक्षरों का पंजीयन, जून 2024 का खाद्यान्न उठाव, 15544 में एमडीएम का एसएमएस करने, वृक्षारोपण करने, शाला भवन की स्थिति सुव्यवस्थित रखने, पेयजल, विद्युतीकरण, अप्रवेशी शाला त्यागी बच्चों का सर्वे कर प्रवेश देने, ओलंपियाड, एनएमएमएस, एनएएस परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई। साथ ही नि:शुल्क सायकिल वितरण सत्र 2023 - 24 जारी राशि के अंतरण की स्थिति तथा सायकिल क्रय उपरांत चेचिस नंबर दर्ज करनें की स्थिति साथ ही 2024-25 हेतु साइकिल हेतु पात्र बच्चों के सत्यापन की समीक्षा की गई। कक्षा 1 एवं 2 के छात्रों का पंजीयन/सत्यापन, अध्यापन कार्य आदि की समीक्षा की गई।

बैठक में माह नवंबर में होने वाले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी हेतु बिंदुवार जानकारी दी गई तथा राज्य शिक्षा केंद्र से उपलब्ध निर्देश (समय सारिणी) से सभी को अवगत कराया गया।

सहायक आयुक्त डॉ. द्विवेदी द्वारा बच्चों का भविष्य संवारने हेतु गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तथा अध्यापन कार्य पर सर्वाधिक जोर दिया गया। कक्षा में शिक्षक बच्चों के बीच सक्रिय रहकर उत्तम अध्यापन कार्य करने, समय से समय तक शाला संचालित करने, शाला तथा शाला परिसर सदा स्वच्छ रखने, कक्षा 1 से 12वीं तक के अच्छे परीक्षा परिणाम हेतु शुरू से ध्यान देने पर विशेष रूप से जोर दिया गया।

एपीसी पाण्डेय द्वारा प्रतिदिन बोलकर लिखाने हेतु प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही लक्ष्य निर्धारित कर शतप्रतिशत छात्रों के लिए योजना बनाकर गुणात्मक सुधार के लिए सफलता प्राप्त करने हेतु सुझाव दिए गए। जिस शाला भवन की स्थिति ठीक नही है, उन शाला भवनों में कक्षाएं संचालित नही किये जाने के निर्देश दिए गए और निर्देशित किया गया कि नजदीकी शासकीय भवन में ही शाला संचालित करे, किसी भी स्थिति में छात्रों की सुरक्षा करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। सभी जनशिक्षकों को प्रतिदिन कम से कम 3 विद्यालय का अवलोकन करनें हेतु निर्देशित किया गया। भविष्य में शैक्षणिक कार्य में लापरवाही करने पर सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत मूलभूत जानकारी प्रदान की गई तथा प्रत्येक शाला प्रभारी को अपने बसाहट क्षेत्र में घर- घर जाकर असाक्षरों का चिन्हांकन करने, साक्षरता पंजी संधारित कर असाक्षरों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में दर्ज करने एवं एनआईएलपी एप में समस्त असाक्षरों का शत प्रतिशत पंजीयन करने हेतु निर्देशित किया गया। आज की बैठक में मध्यान्ह भोजन के नियमित संचालन हेतु विशेष निर्देश दिए गए। साथ ही 15544 में एसएमएस करने तथा प्रतिदिन फोटो भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में एपीसी विष्णु पाण्डेय, एपीसी रजनीश श्रीवात्सव, सहायक यंत्री सत्यप्रकाश तिवारी द्वारा अपने अपने सेक्शन की जानकारी से सभी संस्था प्रमुखों को अवगत कराया गया।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारियो की त्वरित प्रतिक्रिया

प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट जनकल्याण को समर्पित- देव कुमार

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव द्वारा की सरकार द्वारा पेश किया गया बजट जन कल्याण को समर्पित बजट है।बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है।

पेश किया गया बजट प्रदेश की उन्नति में लगाएगी पंख- सांसद डॉ राजेश मिश्रा

सांसद डॉ राजेश मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत किए गए मध्य प्रदेश के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि कर प्रदेश की जनता को सर्वांगीण विकास का तोहफा दिया। प्रस्तुत बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में 21,144 करोड़ से अधिक की वृद्धि कर आगामी 2 वर्षों में 11 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान कर श्रवण कुमार का फर्ज बखूबी निभाएंगे। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन एवं पर्यावरण के लिए 4725 करोड़ का प्रावधान किया है। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि के भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से सेवानिवृत कर्मचारियों को भत्ते तत्काल और सुगमता से मिलेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया बजट का में लोकसभा की जनता जनार्दन की ओर से अभिनंदन करता हूं।

सिंचाई और सड़कों के लिए मिला पर्याप्त बजट- शरदेंदु तिवारी

भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के महामंत्री और पूर्व विधायक शरदेन्दु तिवारी ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि आगामी 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछने जा रहा है, जिसमें अटल प्रगति पथ पर 299 किलोमीटर, नर्मदा प्रगति पथ पर 900 किलोमीटर, विंध्य एक्सप्रेस वे पर 676 किलोमीटर, मालवा निमाड़ विकास पथ 450 किलोमीटर, बुंदेलखंड विकास पथ 330 किलोमीटर और मध्य भारत विकास पथ को 746 किलोमीटर की विश्व स्तरीय सड़के मिलने जा रही हैं केवल इतना ही नहीं किसने की आए दुगना करने के लिए प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र के रकवा एक करोड़ हेक्टेयर से अधिक होने वाला है। वर्तमान में सिंचित क्षेत्र का रकबा 50 लाख है, जिसे आगामी वर्षों में बढ़कर 1 करोड़ हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए बजट में 13596 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट में कोई नया कर नहीं लगाकर, सरकार ने जनता के विकास के लिए खोला नया द्वारा- विधायक रीती पाठक

सीधी विधानसभा की विधायक और पूर्व सांसद श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि विधानसभा में पेश किए गए बजट की मै प्रत्यक्ष साक्षी हूं। विधानसभा में प्रस्तुत किया गया बजट डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। इस बजट में 36,5 67 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट की प्रमुख विशेषता यह रही की इस सत्र में देश की जनता जनार्दन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया है, लेकिन कोई नया कर ना लगाते हुए भी संसाधनों में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हुए प्रदेश को विकसित, समृद्धशाली और जनकल्याणकारी बनाने में कोई कसर कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। जिसके लिए मैं क्षेत्र की जनता की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का अभिनंदन करती हूं। विधायक श्रीमती पाठक ने कहा कि पेश किया गया बजट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ गरीब, युवा, महिला और किसानों का ख्याल रखते हुए उत्तम कोटि का बजट पेश किया गया है।

विद्यार्थियों के लिए पेश किया गया बजट कल्याणकारी- सुरेंद्र मणि

भारत स्काउट एवं गाइड के जिला अध्यक्ष सुरेंद्रमणि दुबे ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट छात्र एवं छात्राओं के लिए कल्याणकारी बजट है, जिसमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए नए-नए विद्यालय, छात्रावास, स्कॉलरशिप एवं निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है।

मोहन सरकार का पहला बजट पेश

जिला हुआ मायूस, नहीं मिली बड़ी सौगात, सिर्फ6 सड़कों और दो पुल को मंजूरी

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली निप्र। मध्यप्रदेश में पेश हो रहे बजट को लेकर विंध्य क्षेत्र के ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले के लोगों को बड़ी उम्मीद थीं। लेकिन सिंगरौली में हवाई पट्टी से हवाई अड्डा बनाने का बजट पास नहीं हुआ। केवल 6 स्थानों पर सड़क और मयार नदी पर दो जगह पूल बनाने की मिली स्वीकृति।

गोपद नदी से करदा, कोल्हुआ से तिनगुड़ी, मजौना से कोहरा खोह, खड़ौरा से जोगनी, गड़वानी से डाला और धनहा गांव में पहुंच मार्ग सड़क बनाने की स्वीकृति मिली।

साथ में मयार नदी पर दो जगह शासन से जरहा और ओखरावल से बहेरी के बीच में पुल बनवाने की स्वीकृति भी मिली।

बाकी सिंगरौली की जनता नया बस स्टैंड,ट्रांसपोर्टनगर की आस लगाए बैठी थी लेकिन उम्मीदों पे पानी फिर गया।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 2061/न.पा.नि./राजस्व/2024-25 रीवा, दिनांक 2/7/24

अचल सम्पति नामांतरण विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व नगर सुधार न्यास रीवा की व्यवसायिक योजना क्रमांक-7 यातायात नगर रीवा जो नगर पालिक निगम रीवा के स्वामित्व में है, में स्थित भूखण्ड क्रमांक s/226 क्षेत्रफल 12.72 वर्गमीटर श्री आसिफ खान पिता सोहराव खान को 30 वर्षीय लीज पर आवंटित है, इनकी मृत्यु पश्चात, इस भूखण्ड का नामान्तरण श्रीमती आमना खान पति स्व. श्री आसिफ खान निवासी राघुराज मार्ग अंजुमन इस्लामिया स्कूल के पास घोघर रीवा (म.प्र.) के नाम किये जाने हेतु दिनांक 05.04.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड क्रमांक s/226 के नामांतरण में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो, तो समाचार पत्रों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि तक कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा में प्रमाणित अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आवेदन/आपत्ति न तो ग्रहण की जावेगी और न ही मान्य की जावेगी। तत्पश्चात आवेदिका के आवेदन अनुसार उक्त भूखण्ड क्र. s/226 का नामांतरण श्रीमती आमना खान पति स्व. श्री आसिफ खान निवासी रघुराज मार्ग अंजूमन इस्लामिया स्कूल के पास घोघर रीवा (म.प्र.) के नाम करने की कार्यवाही की जावेगी।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर पालिक निगम रीवा (म.प्र.)

विचार

पिछड़ा वर्ग के हित में लिए निर्णय लागू करने में ईमानदारी दिखानी होगी

हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में 15 प्रतिशत से 27 प्रतिशत बढ़ोतरी और क्रीमीलेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की है। निश्चित रूप से आपकी सरकार का यह निर्णय सराहनीय और काबिले तारीफ है। इस फैसले से पिछड़ा वर्ग के युवाओं को शिक्षण संस्थानों में अधिक दाखिले हो पाएंगे, साथ ही सरकारी नौकरियों में भी अधिक से अधिक युवाओं को नियुक्ति के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री जी, असली मामला अब शुरू होता है। प्रदेश में इस समय कुल स्वीकृत सरकारी पद साढ़े 4 लाख हैं, जबकि 2.7 लाख नियमित कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। इस प्रकार से राज्य में लगभग पौने 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। इस समय सरकारी स्वीकृत पदों में पिछड़ा वर्ग का 65,000 से भी अधिक पदों का बैकलॉग है। अनुसूचित जाति का लगभग 62,000 बैकलॉग है। इस प्रकार वर्तमान में अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों की बात की जाए तो तृतीय श्रेणी में अभी केवल 12 प्रतिशत पद भरे हुए हैं। द्वितीय श्रेणी में केवल 10 प्रतिशत और प्रथम श्रेणी में लगभग 7 प्रतिशत ही पद भरे हुए हैं। चतुर्थ श्रेणी में तो केवल 4 प्रतिशत पद ही भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, चतुर्थ श्रेणी के स्वीपर के पदों पर तो अनुबंध के आधार पर कर्मचारी लगाए हुए हैं। इन पदों पर कोई भी नियमित कर्मचारी नहीं है। खाली पदों के मुकाबले हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत या सीधे विभागों के जरिए लगभग 1 लाख 18 हजार कर्मचारी बहुत ही कम वेतन पर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति का हजारों की संख्या में बैकलॉग तो है ही, साथ ही हरियाणा रोजगार कौशल निगम की भर्तियों में अभी तक किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा रहा, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बार-बार सार्वजनिक मंचों से व सरकारी आदेश जारी कर कहा जा चुका है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भारतीयों में पिछड़ा वर्ग वह अनुसूचित जाति के युवाओं को आरक्षण मिलेगा। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने तो कई बार अपने वक्तव्यों और भाषणों में यह भी कहा है कि निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में भी हरियाणा के युवाओं को आरक्षण दिया जाएगा, परिणाम अभी तक शून्य है। प्रदेश में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया है, जिसके प्रावधानों के अनुसार, किसी विश्वविद्यालय को हरियाणा के मूल निवासियों के छात्रों के लिए प्रवेश हेतु कम से कम एक-चौथाई सीटें आरक्षित करनी होती हैं, जिनमें से 10 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी लेकिन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा इस अधिनियम की भी पालना नहीं की जा रही। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवालिया निशान उठना वाजिब है। मुख्यमंत्री द्वारा ढोल पीट-पीट कर दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 पदों पर पक्की भर्तियां की जाएंगी। इन भर्तियों में तो लंबी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। जब तक स्वीकृत पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है, तब तक आप पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा की गई भर्तियों में आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के युवाओं की भर्ती तो कीजिए।

मोदी सरकार के कार्यकाल में लोगों का खर्च बढ़ा, आमदनी लुढ़की और बचत घटी

कमलेश पांडे

केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले दो कार्यकाल के मुकाबले तीसरी बार के कार्यकाल के लिए उनकी पार्टी भाजपा को जनादेश कम मिलने का रहस्य उनकी आर्थिक नीतियों में भी छिपा है, जो यह चुगली कर रहा है कि इनके पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में भारत के लोगों की शुद्ध बचत में गिरावट आई है, जबकि खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उनकी सरकार के मातहत काम करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-2024 बोल रही है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले एक दशक यानी मोदी युग में न केवल लोगों की शुद्ध बचत घटी है, बल्कि इसी बीच आई वैश्विक कोरोना महामारी के चलते भी लोगों के बचत करने के व्यवहार में आमूल चूल बदलाव आया है।

यदि मोदी सरकार इसे समय रहते ही समझ गई होती तो उसे गठबंधन की बैशाखी पर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और न ही 400 पार का सपना टूटता। अब बात करते हैं आरबीआई की इस रिपोर्ट की, जिसके मुताबिक, देशवासियों के बीच बचत कम होने के दो मुख्य कारण हैं- पहला यह कि अब लोग सोना-चांदी, जमीन-घर और म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। और दूसरा यह कि, लोगों का घरेलू खर्च यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, आम उपभोग आदि बढ़ा है, जिसकी वजह से शुद्ध वित्तीय बचत में भारी कमी दिखाई पड़ी है। बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सकल बचत दर में सकल शुद्ध प्रयोज्य आय 29.7 प्रतिशत थी। जिसमें परिवार के प्राथमिक बचतकर्ता की हिस्सेदारी 60.9 प्रतिशत रही है, जबकि वर्ष 2013-22 के बीच का औसत 63.9 प्रतिशत रहा। इसी तरह से लोगों के पास शुद्ध वित्तीय बचत में भी 11.3 प्रतिशत की गिरावट आई है जो 2022-23 में गिरकर 28.9 प्रतिशत रह गई है, जबकि 10 वर्षों का औसत 39.8 प्रतिशत रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भले ही घरेलू बचत में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन वह ज्यादा स्थाई नहीं रह पाई। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान कुल घरेलू बचत 51.7 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, परंतु उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला तो लोगों ने अपनी बचत को सम्पत्तियों के खरीदने पर खर्च करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ लोगों की देनदारियों में भी बढ़ोतरी हुई, जिससे नगदी के रूप में बचत गिरती चली गई। वहीं, कोरोना के बाद से लोग बचत को बैंक खातों में एफडी व अन्य रूप में रखने से बच रहे हैं। जबकि सम्पत्तियों को खरीदने के लिए कर्ज लेने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि कृषि और व्यवसायिक लोन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की जीडीपी का 40 प्रतिशत घरेलू उधार हो गया है, जो दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में इंडोनेशिया, मैक्सिको, पौलेंड और ब्राजील से अधिक है। वहीं, आमलोगों के खर्चों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते शुद्ध रूप से वित्तीय बचत में गिरावट आई है। यदि मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल के औसत के हिसाब से भी देखा जाए तो जीडीपी में शुद्ध बचत की हिस्सेदारी 2.7 फीसदी कम हो गई है। कहने का मतलब यह कि एक दशक पहले के आठ प्रतिशत से घटकर यह 2022-23 में 5.3 फीसदी पर आ गई है,जो चिंता की बात है। रिपोर्ट बताती है कि अब लोगों को शेयर बाजार से अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जो किसी भी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज से कहीं ज्यादा है। सामान्य तौर पर बैंकों में सात से आठ प्रतिशत का सालाना रिटर्न मिल रहा है, लेकिन शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों को मोटा रिटर्न मिला है। खासकर निफ्टी में पैसा लगाने वालों को ठीक-ठाक रिटर्न मिला है। आंकड़े बता रहे हैं कि जहां निफ्टी 50 में पहले वर्ष 29 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 13 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 15 प्रतिशत का रिटर्न मिला है, वहीं निफ्टी मिडकैप 150 में पहले वर्ष 56 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 26 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 25 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 250 में पहले वर्ष 63 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 23 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 28 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। जबकि निफ्टी माइक्रोकैप 250 में पहले वर्ष 85 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 37 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 42 प्रतिशत का रिटर्न मिला है।

नये भारत में बदलाव के कानून, जल्द मिलेगा न्याय

भारतीय न्याय प्रणाली की कमियां को दूर करते हुए उसे अधिक चुस्त, त्वरित एवं सहज सुलभ बनाना नये भारत की अपेक्षा है। मतलब यह सुनिश्चित करने से है कि सभी नागरिकों के लिये न्याय सहज सुलभ महसूस हो, कानूनी प्रावधान न्यायसंगत एवं अपराध-नियंत्रण का माध्यम हो, वह आसानी से मिले, जटिल प्रक्रियाओं से मुक्त होकर सस्ता हो। निश्चित रूप से किसी भी कानून का मकसद नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति व अधिकारों की रक्षा करना ही होता है। जिससे किसी सभ्य समाज में न्याय की अवधारणा पुष्ट हो सके। 1 जुलाई, 2024 से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। न्याय का एक नया सूरज उदित हो रहा है, जब पूरे देश में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य संहिता को लेकर उम्मीद करनी चाहिए कि यह बदलाव न्याय की कसौटी पर खरा उतरेंगे। इस दृष्टि से यह कानून से जुड़ी अकल्पित उपलब्धियों से भरा-पूरा अवसर भारत न्याय प्रक्रिया को एक नई शक्ति, नई ताजगी और नया परिवेश देने वाला साबित होगा। उल्लेखनीय है कि कानूनी बदलाव से जुड़े ये तीनों विधेयक बीते साल संसद में पारित किये गए थे। अंग्रेजों के बनाये कानून क्या स्वतंत्र भारत में साढ़े सात दशक बाद भी लागू रहने चाहिए, यह लम्बे समय से विमर्श का विषय बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी, आधुनिक, तकनीकी बनाने के लिये, अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को बदलने एवं आधुनिक अपेक्षाओं के नये कानून बनाने का साहसिक एवं प्रासंगिक कदम उठाते हुए नए कानून लाने एवं उन्हें लागे करने का बड़ा कदम उठाया है, जो सुखद एवं स्वागतयोग्य है। विपक्षी दलों ने सांस्कृतिक, धार्मिक व भौगोलिक विविधता वाले देश के लिये बनाये गये कानूनों को भले ही व्यापक सार्वजनिक विमर्श के बाद ही लागू किया जाने की अपेक्षा व्यक्त की हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जहां ब्रिटिश काल में बने कानूनों का मकसद दंड देना था, वहीं नये कानूनों का मकसद नागरिकों को न्याय देना है। मौजूदा चुनौतियों व जरूरतों के हिसाब से कानूनों को बनाया गया है। इन कानूनों को बनाने का मूल उद्देश्य अपराधमुक्त समाज की संरचना करना है। इसीलिये अपराधियों को कड़े दण्ड देने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय न्याय संहिता में विवाह का प्रलोभन देकर छल के मामले में दस साल की सजा, किसी भी आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा, लूटपाट व गिरोहबंदी के मामले में तीन साल की सजा का प्रावधान है। आतंकवाद पर नियंत्रण के लिये भी कानून है। किसी अपराध के मामले में तीन दिन में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा सुनवाई के बाद 45 दिन में फैसला देने की समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं प्राथमिकी अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के जरिये दर्ज की जाएगी। व्यवस्था की गई है कि लोग थाने जाए बिना भी ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कर सकें। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इन कानूनों के माध्यम से देश में पुलिस सुधार को भी बल मिलेगा। पुलिस कानून-कायदे के तहत काम करने को विवश या बाध्य होगी। अंतत: अब पुलिस को अनुशासित बनाने के साथ-साथ कारगर बनाने की ओर देश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पुलिस प्रशासन की सफलता इसी में है कि तमाम लोगों को यह महसूस हो कि कानून न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जा रहा है। एक पहलू यह भी है कि पुलिस प्रशासन को कुशल और सक्षम बनाने के लिए संसाधनों की कमी आड़े नहीं आए। जिस स्तर की सेवा की उम्मीद लोग पुलिस से कर रहे हैं, उसके लिए सरकारों को पुलिस पर व्यय बढ़ाना होगा। सक्षम और सहयोगी पुलिस हमारे तेज विकास में कारगर होगी। पुलिस को प्रशिक्षित एवं सक्षम बनाने के तंत्र भी नये तरीके से विकसित करने होंगे। एक तरह से इन कानूनी प्रावधानों को सहज एवं सरल बनाने के प्रयास किये गये हैं। ध्यान रहे, पिछले कानूनों में यह बड़ी कमी थी कि वे गरीबों को न्याय दिलाने में असमानता के द्योतक थे। उन कानूनों का इस्तेमाल गरीबों के खिलाफ जितनी आसानी से होता था, उससे कहीं ज्यादा कठिनाई से अमीरों के खिलाफ मामले दर्ज होते थे।

भारत में शारीरिक निष्क्रियता का बढ़ना चिन्ताजनक

ललित गर्ग

भारत में बढ़ती शारीरिक अकर्मण्यता एवं आलसीपन एक समस्या के रूप में सामने आ रहा है, लोगों की सक्रियता एवं क्रियाशीलता में कमी आना एवं वयस्कों में शारीरिक निष्क्रियता का बढ़ना चिन्ता का सबब है। इस दृष्टि से प्रतिष्ठित लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की वह हालिया रिपोर्ट आईना दिखाने वाली है जिसमें पचास फीसदी भारतीयों के शारीरिक श्रम न करने का उल्लेख है। महिलाओं की स्थिति ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। उनकी निष्क्रियता का प्रतिशत 57 है। वैसे अकेले पुरुषों की निष्क्रियता का प्रतिशत 42 है। इस अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर वर्तमान में तेजी से पसर रहा आलसीपन एवं शारीरिक निष्क्रियता इसी तरह जारी रहा तो 2030 तक भारत में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता वाले वयस्कों की संख्या बढ़कर साठ प्रतिशत तक पहुंच जायेगी, जो चिन्ताजनक है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आधी वयस्क आबादी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के शारीरिक गतिविधि संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के वयस्कों में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता का पैमाना 2000 में 22.3 फीसदी से बढ़कर 2022 में 49.4 फीसदी हो गई है, साथ ही इसमें बताया गया है कि देश में महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा शारीरिक रूप से ज्यादा निष्क्रिय हुई हैं। इस निष्क्रियता, आलसीपन एवं उदासीनता का कारण बढ़ते उपभोक्तावाद एवं शहरीकरण से उपजी सुविधावादी एवं आरामदायक जीवनशैली है। इसके कारण बीमारियां भी बढ़ रही है। क्योंकि जब व्यक्ति को सुस्त, निढ़ाल एवं निस्तेज देखा जाता है तो इसका सीधा अर्थ यही लगाया जाता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। विडम्बना यह भी है कि समय के साथ विस्तृत होने दायरे के बीच ज्यादातर लोगों की व्यस्तता तो बढ़ी है, मगर उनकी शारीरिक सक्रियता, उत्साह एवं जोश में तेजी से कमी आई है, जो नये बनते भारत एवं सशक्त भारत के निर्माण के संकल्प के सामने एक बड़ी चुनौती है। भविष्य के भारत को लेकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की साठ प्रतिशत आबादी अगर शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं रहे तो आने वाले वक्त में यहां की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से कैसी तस्वीर बनेगी। जिस देश की अधिकांश आबादी के सामने रोजी-रोटी की समस्या जटिल एवं अहम है, वहां के लोगों को जीवन चलाने के लिये शारीरिक रूप से जरूरत से ज्यादा सक्रिय रहते हुए श्रम करना पड़ता है। इन स्थितियों में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि भारत में ऐसे हालात कैसे पैदा हो रहे हैं कि यहां इतनी बड़ी आबादी सुस्त एवं आलसी होती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत एशिया प्रशांत में उच्च आय वर्ग वाले देशों में निष्क्रियता के क्रम में दूसरे स्थान पर है। निस्संदेह, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की हालिया रिपोर्ट आंख खोलने वाली है, रिपोर्ट गंभीर चिन्तन-मंथन की आवश्यकता को भी उजागर कर रही है।। यह जानते हुए भी कि भारत लगातार मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों में जकड़ता हुआ बीमार राष्ट्र बनता जा रहा है। इन असाध्य बीमारियों का कारण कहीं-न-कहीं श्रम की कमी एवं सुविधावादी जीवनशैली ही है। दरअसल, आजादी के बाद देश में आर्थिक विकास को गति मिली है। अब हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। औसत भारतीय के जीवन स्तर में सुधार जरूर आया है तो आम नागरिक का जीवन सुविधावादी भी बना है। इस

संकट की वजह शहरीकरण और जीवन के लिये जरूरी सुविधाओं का घर के आस-पास उपलब्ध हो जाना भी है, आनलाइन प्रचलन भी बड़ा कारण बन रहा है। पहले देश की साठ फीसदी से अधिक आबादी कृषि व उससे जुड़े श्रमसाध्य कार्यों में सक्रिय थी। लेकिन अब मेहनतकश किसान को कोई शारीरिक श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कृषि की ही तरह अन्य श्रम से जुड़े कार्यों में भी मेहनत एवं श्रम पहले ही तुलना में कम करना पड़ता है क्योंकि धीरे-धीरे कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में आधुनिक यंत्रों व तकनीकों ने शारीरिक श्रम की महत्ता को कम किया है। कृषि-क्रांति से बड़ी संख्या में निकले लोगों ने शहरों को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन वे शारीरिक सक्रियता को बरकरार नहीं रख पाये। इन स्थितियों ने भी व्यक्ति को आलसी, अकर्मण्य एवं सुस्त बनाया है। इस शारीरिक निष्क्रियता के मूल में भारतीय पारिवारिक संरचना व सांस्कृतिक कारण भी हैं। घर-परिवार संभालने वाली महिलाओं में भी बढ़ते सुविधा के साधनों के कारण श्रमशीलता कम हुई है। कुछ दूर पर सब्जी-फल लेने जाने पर भी हम वाहनों का इस्तेमाल करते हैं।

ऐसा भी नहीं है कि शहरों में स्वास्थ्य चेतना का विकास नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद शहरों के पार्कों में सुबह गिने-चुने लोग ही नजर आते हैं। व्यक्तियों में प्रात: भ्रमण, योग, ध्यान, व्यायाम की गतिविधियों में भी कमी देखने को मिल रही है। इस जटिल से जटिलतर होती समस्या से मुक्ति के लिये हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। खुद को छोटी-मोटी असुविधाओं के लिए तैयार करना होगा। कभी-कभार थोड़ा कम नींद लेने, कम खाने या फिर ज्यादा देर काम कर लेने की मानसिकता को बल देना होगा। जरा सी चुनौती सामने आने पर बेचैन न हों, उसे नया सीखने के मौके व नए अनुभव के रूप में देखना होगा। अक्सर जब कुछ नया करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो पुरानी आदतें एवं आराम की मानसिकता तुरंत परीक्षा लेने आ जाती हैं। हमें ललचाती हैं या फिर खुद को थोड़ा ढील देने के लिए कहती हैं। मन भी खुद को बड़ी आसानी से समझाने लगता है कि कुछ देर और सो जाने, और मीठा खा लेने, फोन पर बात करने या काम को कल पर टालने से कुछ गड़बड़ नहीं होगा। कुल मिलाकर हम मन के बहकावे में आने लगते हैं और खुद को छूट देने लगते हैं जो हमें सुस्त, आलसी एवं निस्तेज बनाता है। विचित्र स्थिति यह भी है कि लोगों में व्यस्तता में एक अजीब किस्म की बढ़ोतरी हुई, जीवन व्यस्त से ज्यादा अस्त-व्यस्त हुआ है। जरूरी कामों को छोड़कर तमाम लोग रोजाना पांच से सात घंटे या इससे भी ज्यादा समय अपने स्मार्टफोन या अन्य तकनीकी संसाधनों, सोशल मीडिया एवं अन्य आभासी मंचों पर समय बर्बाद करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान वर्क फरोम हॉम का प्रचलन बढ़ा, उसने भी लोगों को ज्यादा शिथिल होने में भूमिका निभाई है। देर राज तक जगना एवं सुबह देर तक सोना, इस तरह बिगड़ती दिनचर्या एवं शरीर की प्राकृतिक घड़ी का चक्र बिगड़ने से दिन भर आलस्य बना रहता है। ताजा अध्ययन में पता चला कि 195 देशों में भारत अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता के मामले में 12वें स्थान पर है। इसके अलावा, लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर एक तिहाई वयस्क लगभग 1.8 बिलियन लोग 2022 में अनुशंसित शारीरिक सक्रियता को पूरा करने में विफल रहे। जिसके कारण मधुमेह एवं हृदय रोग का खतरा मंडरा रहा है।

अफेयर के शक में पत्नी को काट डाला

लोगों से बातचीत करते देखा तो भड़का पति, फावड़े से किया कई वार

मीडिया ऑडीटर, कोरबा एजेंसी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मंगलवार शाम को पति ने अफेयर के शक में पत्नी को फावड़े से वार कर मार डाला। बताया जा रहा है कि पति ने घर के आंगन में ही वारदात को अंजाम दिया, इस दौरान पूरा फर्श लहू से सना मिला। हत्या के बाद आरोपी ने लाश को खेत में फेंक दिया। पूरी वारदात कोरबी चौकी क्षेत्र के जल्के गांव का है।

मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी कत्ल के बाद मौके से भाग गया था। आरोपी पति का नाम बसंत पोया (35) और मृतका का नाम मंगली बाई (32) हैं।

आंगन में गांव वालों से बात करने पर विवाद: बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम मंगली बाई जंगल से बकरी चराकर घर लौटी थी। इस दौरान वह घर के आंगन में गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी। इस बात से महिला का पति गुस्से से आग बबूला हो गया।

फावड़े से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार: दोनों के बीच विवाद होता देख जो लोग वहां खड़े थे, वहां से चले गए। पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बंसत पोया ने घर में रखे फावड़े से मंगली बाई पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। खून से लहूलुहान महिला बेहोश होकर गिर गई, जो दोबारा नहीं उठी।

लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया: स्थानीय लोगों ने बताया कि जब हम लोग पहुंचे तो आंगन पर महिला मरी पड़ी थी। इसकी सूचना कोटवार ने कोरबी चौकी पुलिस को दी। मौके से पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी को गांव से ही घेराबंदी कर पकड़ा।

अफेयर के शक में हत्या: एएसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूपीएस चौहान ने बताया कि महिला के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मौका-ए-वारदात से फावड़े को जब्त किया गया है। प्रथम जांच के दौरान अफेयर के शक में हत्या करने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर ही है।

बांध में डूबी किसानों की 250 एकड़ जमीन

1988 से कर रहे मुआवजे की मांग, कलेक्टर से की मुलाकात

मीडिया ऑडीटर, खैरागढ़ एजेंसी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के किसान मुआवजे के लिए सालों से प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ग्राम परसबोड और उरईडबरी के किसान अपनी डुबान खेती की जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अब तक किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली है।

क्षेत्र के किसान एक बार फिर खैरागढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों ने अपनी समस्या को लेकर एडीएम प्रेम कुमार पटेल को ज्ञापन सौंपा।

किसानों की जमीन लगातार डूबती जा रही: साल 1988 में ग्राम उरईडबरी के पास नदी पर बांध बनाया गया था। पीड़ित किसान नीलेश्वर साहू ने कहा कि बांध के क्षेत्र के किसानों की जमीन लगातार डूबती जा रही है। बांध का आकार बढ़ने से किसानों के खेत भी डुबान क्षेत्र में आ रहे हैं। अब तक किसानों की लगभग 250 एकड़ जमीन डुबान क्षेत्र में आ गई है।

एडीएम प्रेम कुमार पटेल से की मुलाकात: ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में ।क्ड प्रेम कुमार पटेल से मुलाकात की। उन्होंने कलेक्टर से जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की गई है।

जांच के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई: पूरे मामले में एडीएम प्रेम कुमार पटेल ने कहा कि इस जलाशय के लिए किसानों के जमीन का अधिग्रहण 1988/89 में किया गया था। अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा नहीं मिलने की बात किसानों ने कही है। आवेदनों और दस्तावेजों की जांच अनुभागीय अधिकारी से कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर रेंज साइबर थाने में नए प्रभारी की नियुक्ति

आईजी के आदेश पर 14 पुलिसकर्मियों की नई टीम गठित, धोखाधड़ी के मामले सुलझने में आएगी तेजी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर एजेंसी। रायपुर रेंज साइबर थाने में नए प्रभारी की नियुक्ति हो गई है। रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा के आदेश पर 14 पुलिसकर्मियों के साथ एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में नई टीम का गठन किया गया है। इन पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद जिले से रायपुर में किया गया है।

इसके अलावा, मनोज नायक प्रभारी शिकायत शाखा को साइबर प्रभारी रेंज भी बनाया गया है। इस नई टीम के गठन के साथ ही उम्मीद है कि लोगों के साथ साइबर ठगी के मामले सुलझने में तेजी आएगी।

घर में घुसकर चुराया महुआ, 3 गिरफ्तार

मोबाइल और वाटर मोटर भी बरामद, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

मीडिया ऑडीटर, सूरजपुर एजेंसी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में चोरी के 3 आरोपियों को रामानुजनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का 1 मोबाइल, 3 बोरी महुआ और वाटर मोटर जब्त किया है। जिसकी कुल कीमत 15 हजार रुपए है।

बीते 1 जुलाई को भुवनेश्वरपुर गांव के रामसुभग साहू ने थाना रामानुजनगर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि 28-29 जून 2024 की रात में घर में घुसकर कोई अज्ञात चोर मोबाइल, 3 बोरी महुआ और 1 टुल्लू पंप चोरी कर ले गया।

पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा: मामले की जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति टुल्लू पंप बेचने के लिए सूरजपुर की ओर जा रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर घेराबंदी कर नारायणपुर से व्यक्ति को टुल्लू पंप के साथ पकड़ा। व्यक्ति ने अपना नाम घिरेन्द्र सिंह बताया।

चोरी का सामान बरामद किया गया: पूछताछ पर उसने बताया कि उसने अपने साथी महेश चौबे और बैजू कुर्रे के साथ मिलकर मोबाइल, महुआ और टुल्लू पंप चोरी कर आपस में बांट लिए है, जिसके बाद पुलिस ने 2 और आरोपी को दबिश देकर पकड़ा।

आरोपी घिरेन्द्र सिंह (23), महेश चौबे (27) और बैजू कुर्रे (34) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के निशानदेही पर चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम द्वारा डेयरी दुकानों का किया जा रहा सतत् निरीक्षण

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी निप्र। जिले में नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार डेयरी दुकानों का सतत् एवं सघन निरीक्षण किया जा रहा है।

मिलावट की आशंका के मद्देनजर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता एवं उनकी टीम द्वारा मेसर्स कृष्णा डेयरी अग्रवाल लॉज रोड मनेन्द्रगढ़ से पनीर और मेसर्स हनुमान डेयरी फार्म, वार्ड नं. 17 जे .के.ड़ी रोड मनेन्द्रगढ़ से गाय का दूध का विधिक नमूना जब्त कर परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर से परीक्षण् विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और नियम 2011 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यह कदम उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।

80 कॉलेजों में एडमिशन की चयन सूची जारी

गर्ल्स पीजी और आत्मानंद कॉलेजों में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग का कटऑफ मार्क्स 65 प्रतिशत

मीडिया ऑडीटर, सरगुजा एजेंसी। सरगुजा के संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के तहत संचालित 80 कॉलेजों में न्ळ के 4 साल के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसे जारी करने में एक दिन की देरी हुई। शासकीय कॉलेजों में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सभी संकायों में प्रवेश के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

गर्ल्स पीजी कॉलेज और आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम पीजी कॉलेज में सभी संकायों में कटऑफ मार्क्स 65 प्रतिशत या इससे अधिक है। संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी में 30 हजार सीटें हैं। अब तक 27 हजार से अधिक छात्रों ने प्रवेश के लिए पंजीयन किया है। यूनिवर्सिटी ने पंजीयन के लिए पोर्टल 18 जून से 30 जून तक खुला था।

दो कॉलेजों में प्रवेश आसान नहीं: यूनिवर्सिटी के आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम पीजी कॉलेज और गर्ल्स पीजी कॉलेज में प्रवेश के लिए सर्वाधिक कटऑफमार्क्स आए हैं। सरकारी कॉलेज होने के बाद भी बेहतर सुविधा होने के कारण इन कॉलेजों में ज्यादा आवेदन भी आए हैं। राजमोहनी देवी गर्ल्स कॉलेज में बीए की 400 सीटों में प्रवेश के लिए 600 आवेदन आए हैं।

बीए सामान्य वर्ग का कटऑफ मार्क्स 65.6 प्रतिशत, ओबीसी का 57 प्रतिशत, एससी का 39 और एसटी वर्ग का कटऑफ55 प्रतिशत है। बीएससी मैथ्स में सामान्य वर्ग का कटऑफ 69.2, ओबीसी का 53, एसटी का 52.7 और एससी का 59.8 प्रतिशत है। बीएससी बायो में सामान्य वर्ग का कटऑफ मार्क्स 71.8 प्रतिशत है। वहीं, बी.काम में सामान्य वर्ग का कटऑफ मार्क्स 72.2 प्रतिशत है।

स्वामी आत्मानंद में भी हाई कटऑफ: स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम पीजी कॉलेज में सभी संकायों में 50-50 सीटें हैं। बीएससी बायो में सामान्य वर्ग का कटऑफ मार्क्स 67.8 प्रतिशत, ओबीसी का 72 प्रतिशत, एसटी का 66.2 प्रतिशत है। माइक्रोबायोलॉजी में सामान्य वर्ग का 68.2, एसटी का 55 और ओबीसी का 50 प्रतिशत कटऑफ है। बायोटेक में सामान्य वर्ग का 70, ओबीसी का 59 व एसटी का 51 प्रतिशत कटऑफगया है।

मैथ्स में सामान्य वर्ग का कटऑफ मार्क्स 66.6 प्रतिशत, एसटी का 50 प्रतिशत और ओबीसी का कटऑफ55 प्रतिशत है। बीएससी आईटी में सामान्य वर्ग का 65 प्रतिशत, एसटी का 50, ओबीसी का 55 प्रतिशत गया है।

आत्मानंद कॉलेज में एससी वर्ग से आवेदन नहीं: आत्मानंद कॉलेज में यूजी के बीएससी आईटी, मैथ्स, माइक्रोबायोलाजी और बायोटेक संकायों में एससी वर्ग से कोई भी आवेदन नहीं आया है। कॉलेज में हर वर्ग में छह-छह सीटें हैं। मेरिट लिस्ट जारी कर कॉलेजों में चस्पा भी कर दिया गया है।

जांच के बाद मिलेगा प्रवेश: यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि, मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों की सूची कॉलेजों में चस्पा कर दी गई है। 10वीं-12वीं की अंकसूची, जाति प्रमाणपत्र, टीसी, पंजीयन की कॉपी और चरित्र प्रमाणपत्र के साथ छात्र कॉलेजों में आकर प्रवेश ले सकते हैं। दस्तावेजों की जांच के लिए समिति बनाई गई है। छात्रों को फोटो और आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी।

अवैध तरीके से खैर पेड़ों की कटाई

वन परिसर से 500 मीटर की दूरी पर भंडारण, बिहार का तस्कर गिरोह एक्टिव

मीडिया ऑडीटर, बलरामपुर एजेंसी। बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र धमनी के सुंदरपुर गांव के आसपास में बड़ी संख्या में अवैध तरीके से खैर की लकड़ी की कटाई हो रही है। बताया जा रहा है कि तस्करों ने कटाई कर लगभग 10 से 12 ट्रैक्टर लकड़ियों को सुंदरपुर नर्सरी में भंडारित किया है।

जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र धमनी रेंज के सुंदरपुर गांव में इन दिनों अंतरराज्यीय लकड़ी तस्कर गिरोह काफी सक्रिय है, जो रात के अंधेरे में लकड़ी की अवैध कटाई कर फॉरेस्ट की भूमि में भंडार करते हैं। हैरानी की बात यह है कि वन भूमि में भंडारीत लकड़ी पर अब तक फॉरेस्ट विभाग की नजर नहीं पड़ी है।

बिहार के तस्कर हैं बेखौफ: बताया जा रहा है कि बिहार के तस्कर लाखों रुपए की खैर की लकड़ी की तस्करी बेखौफहोकर कर रहा है। लकड़ी की कटाई वन परिसर से 500 मीटर की दूरी पर जंगल में डंप किया गया है।

खैर की लकड़ी गांव वालों का कहना है बिहार के तस्कर कुछ दिनों से यहां के लड़कियों को कटवा रहे हैं और वन विभाग नहीं कर रहा कोई कार्यवाही।

अवैध तरीके से खैर की लकड़ी की कटाई: जंगल में पेड़ों की कटाई रात के अंधेरे में की जा रही है. लेकिन इन लकड़ियों को तस्कर जंगल में ही रखे हुए हैं. सुंदरपुर नर्सरी में 10 से 12 ट्रैक्टर से ज्यादा लकड़ियों का भंडारण किया गया है। मामले में फॉरेस्ट विभाग और राजस्व विभाग मामले में चुप्पी साधे हुए है।

लकड़ी भंडारित की गई है, उसकी जांच कराई जा रही: मामले में जब हमने वन परिक्षेत्र के रेंजर अजय वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि जहां भी लकड़ी भंडारित की गई है, उसकी जांच कराई जा रही है। मामले में क्षेत्र के तहसीलदार को भी पत्र लिखा गया है, जितने भी लकड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से या लावारिस हालत में बरामद होंगे, उन्हें जब्ती की जाएगी।

कपरमेटा बांध में मुरुम का अवैध खनन

जितनी अनुमति, उससे ज्यादा खुदाई, खनिज अधिकारी ने कही जांच की बात

मीडिया ऑडीटर, बालोद एजेंसी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के कपरमेटा बांध डुबान क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर मुरुम का खनन किया जा रहा है। खनन की जितनी अनुमति है, उससे ज्यादा का खनन और परिवहन किया जा चुका है। पूरे मामले में खनिज विभाग ने जांच की बात कही है।

जिला खनिज अधिकारी मीनाक्षी साहू ने बताया कि गोपाल राठी के नाम से लीज जारी किया गया है और 2 हजार घन मीटर खुदाई की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि उससे ज्यादा खुदाई की बात सामने आ रही है तो हम खनिज निरीक्षक को भेज कर वहां मामले की जांच करवाएंगे।

चौन माउंटेन लगाकर मुरुम का खनन: मुरुम के खनन के लिए चौन माउंटेन की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके ठेकेदार बाकायदा चौन माउंटेन लगाकर वहां से मुरुम का खनन कर रहा है। खनिज अधिकारी मीनाक्षी साहू ने चौन माउंटेन से खुदाई की अनुमति से इनकार किया है।

जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई: उन्होंने कहा कि यदि चौन माउंटेन से खुदाई की जा रही है तो इस मामले की भी जांच कराई जाएगी। बता दें कि कुछ दिनों से मौके पर चौन माउंटेन से मुरुम का खनन किया जा रहा है और 12 चक्के वाले हाइवा भी काम में लगाए गए हैं।

मॉनिटरिंग के अभाव में अवैध खनन: खनिज विभाग अक्सर लीज या फिर खनन की अनुमति तो देता है, लेकिन इसके बाद मॉनिटरिंग के अभाव में नियमों को ताक पर रखकर खनन कर दिया जाता है। कुछ जगह की अनुमति लेकर आसपास के पूरे क्षेत्र को खोद दिया जाता है। इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सिंगल यूज प्लास्टिक थैली प्रतिबंध दिवस प्लास्टिक प्रकृति के साथ जनजीवन के लिए हानिकारक

प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग को करें कम अपनाएं 3आर

मीडिया ऑडीटर, मनेंद्रगढ़ निप्र। कलेक्टर डी राहुल वेंकट के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में जिले की अखराडाड़, मझोली, कोटिया, आमाडाड़ परसगढ़ी मलकाडोल गोविंदपुर चौनपुर सहित जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध हेतु जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई ग्राम पंचायत कठोतिया में जिला परियोजना निर्देशक नितेश उपाध्याय ने सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रिणामो को ग्रामीणों एवं छात्र छात्राओं से साझा किया ग्राम पंचायत को मॉडल बनाने के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है की रिसोर्स सेग्रिकेशन को अपनाने साथ ही प्लास्टिक प्रतिबंध हेतु जागरूक बने घरेलू गंदे पानी का

उचित प्रबंधन आवश्यक है ,सिंगल प्लास्टिक प्रतिबंध हेतु विद्यालय के छात्र.छात्राओं के द्वारा रैली एवं निबंध लेखन कार्य किया गया साथ ही ग्राम पंचायत में कपड़े के थैली , डस्टबिन का वितरण किया गया प्लास्टिक के दुष्परिणाम हेतु दीवार लेखन किया गया परियोजना निदेशक ने बताया की विदित हो कि 3.3 मेट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रतिवर्ष निकलता है सिंगल यूज प्लास्टिक की बढ़ती उपयोग के कारण प्रतिवर्ष लगभग लाखों लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से काल के गाल में समा जा रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक जहां एक और मिट्टी को बंजर और जल प्रदूषण का बहुत बड़ा कारक बनता जा रहा है वहीं दूसरी ओर वायुमंडल में भी वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा घटक है आज सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग के कारण अनेक जीव जंतु पशु पक्षियों की मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण सिंगल यूज प्लास्टिक है इसकी रोकथाम के लिए हमें 4 आर कांसेप्ट को अंगीकार करना होगा जिसमें रिड्यूस रियूज रिकवर और रीसायकल आयाम को अंगीकार कर अपने दैनिक उपयोग में सिंगल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की आवश्यकता है ।बदले अपना व्यवहार बाजार जाते समय कपड़े एवं जट का थैला साथ लेकर चलें घर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्लास्टिक की दोना कटोरी चम्मच प्लेट थाली चम्मच डिस्पोजल का उपयोग न कर दोना पत्तल का उपयोग करें, ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बर्तन बैंक प्रारंभ करें, सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियां का उपयोग न करें, बिक्री पड़े प्लास्टिक को जमीन के अंदर न दबाए और न जलाएं ,सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने घर पर एकत्रित कर स्वच्छगृही वाहनों को दें प्लास्टिक को न कहे, अपने गांव में सिंगल प्लास्टिक के, प्रतिबंध हेतु स्वयं संकल्पित हो एवं दूसरों को भी जागरूक करें

उक्त आयोजन में राजेश जैन जिला समन्वयक सरपंच श्रीमती सीमा ग्राम पंचायत कठोतिया सचिव भुनेश्वर सिंह स्कूल स्टाफ के साथ क्लस्टर समन्वयक प्रभा प्यासी नेहा ठाकुर सुभाष परस्ते उपस्थित रहे।

हवाला कारोबारी नीरू भाई के ठिकाने पर रेड

महादेव सट्टा-खाईवालों की रकम करता है डिलीवर 80 लाख बरामद, देशभर में दफ्तर

मीडिया ऑडीटर, भिलाई एजेंसी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने हवाला कारोबारी नीरू भाई के रायपुर स्थित ठिकाने पर छापा मारा। टीम ने मौके से 80 लाख रुपए जब्त करने के साथ ही 3-4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीरू भाई महादेव सट्टा ऐप समेत कई ऑनलाइन ऐप और ऑनलाइन सट्टा खाइवालों की रकम हवाला के जरिए भेजता है।

एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की एएसपी ऋचा मिश्रा के नेतृत्व में मंगलवार रात करीब 10.30 बजे रायपुर के शंकर नगर खम्हारडीह स्थित नीरू भाई के दफ्तर पर छापा मारा गया। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हालांकि नीरू भाई अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है।

बताया जा रहा है कि, नीरू भाई मुंबई में बैठकर देश के अलग-अलग ठिकानों में खुले अपने दफ्तर ऑपरेट करता है। वहां से हवाला की रकम कई जगह ठिकाने लगाई जाती है। ।

हैदराबाद में पकड़े गए आरोपियों ने दी नीरू भाई की जानकारी: दरअसल, दुर्ग पुलिस ने हैदराबाद में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के बड़े पैनल का भंडाफोड़ किया था। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला था कि, खाइवालों के करोड़ों रुपए नीरू भाई के जरिए रायपुर और भिलाई भेजे जाते हैं। इसके बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने छापा मारा है।

इंडोनेशिया में महिला को 30 फुट के अजगर ने निगला, सांप का पेट काटकर निकाला शव

बच्चे के लिए दवा लेने गई थी

इंडोनेशिया (एजेंसी)। इंडोनेशिया में एक महिला को 30 फुट लंबे अजगर ने निगल लिया। न्यूज एजेंसी ऱ्स्क्र के मुताबिक घटना सुलावेसी प्रांत के सितेबा गांव की है। महिला का नाम सिरियाती है, जो मंगलवार की सुबह अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने गई थी। लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटी।

जब सिरियाती कई घंटों बाद भी नहीं लौटी तो उसके पति आदियासा ने उसे ढूंढना शुरू किया। आदियासा को घर से 500 मीटर की दूर पर उसकी चप्पल और कपड़े के टुकड़े मिले। इसके बाद उसने पुलिस के पास गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सिरियाती को ढूंढने लगी। इस दौरान उन्हें घर के रास्ते से 10 मीटर दूर पर एक लंबा अजगर दिखाई दिया। अजगर का पेट का काफी मोटा दिखाई दे रहा था। इसके बाद लोगों ने अजगर का पेट काटकर महिला की लाश बाहर निकाली।

पिछले महीने भी एक अजगर ने महिला को निगला था : स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले महीने भी इस इलाके में 50 साल की फरीदा को अजगर ने निगल लिया था। फरीदा बाजार जाते समय लापता हो गई थी। दो दिन बात उसे अजगर के पेट से निकाला गया। अब सिरियाती का शव मिलने से लोग दहशत में है। पिछले साल भी एक अजगर ने एक किसान को निगल लिया था। इसके बाद लोगों ने उस 4 मीटर लंबे अजगर को मार डाला था। सुलावेसी के मुना शहर में 2018 में एक 54 साल की महिला को 7 मीटर लंबे अजगर ने निगल लिया था। लोगों ने बताया कि शहर का रास्ता जंगल से होते हुए जाता है इसलिए यहां इस प्रकार घटनाएं होती हैं।

हाथरस सत्संग कांडः रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भगड़द में लोगों की मौत पर जताई संवेदना

मॉस्को (एजेंसी)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र में आयोजित सत्संग में लोगों की जान जाने पर शोक व्यक्त किया। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हुई है। भारत में रूसी दूतावास ने 'एक्स पर एक पोस्ट में कहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर प्रदेश में हुई दुखद भगदड़ पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शोक संदेश भेजा- कृपया उत्तर प्रदेश में हुई दुखद दुर्घटना पर हार्दिक संवेदना स्वीकार करें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को सत्संग के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।भगदड़ मची भगदड़ के बाद हुई मौत का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया है। घटना को लेकर दाखिल लेटर पिटीशन डाली गई है।अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को लेटर पिटीशन भेजा है। लेटर पिटीशन में पूरी घटना की सीबीआई या न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने घटना में जिम्मेदार अफसरों को सस्पेंड करने और लोगों की मौत की जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पूरे मामले की जांच स्पेशल इंस्टिगेटिव एजेंसी से कराए जाने का आदेश दिए जाने की भी मांग की गई है

स्थिरता और मानवाधिकार अनुपालन के लिए ह ने की भारत की व्यावसायिक प्रथाओं की प्रशंसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की व्यावसायिक प्रथाओं की प्रशंसा की है, जिसमें स्थिरता पर उनके फोकस को उजागर किया गया है, जिसे दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में निवेश के माहौल के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्तुत मानवाधिकार और बहुराष्ट्रीय निगमों और अन्य व्यावसायिक उद्यमों के मुद्दे पर कार्य समूह की एक रिपोर्ट में आई है। रिपोर्ट में विशेष रूप से भारत की व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्टिंग पहल की प्रशंसा की गई है, जो बड़े, सूचीबद्ध व्यवसायों के लिए एक अनिवार्य प्रकटीकरण ढांचा है। इसे एक उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में उद्धृत करते हुए, इसने कहा, भारत में व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्टिंग पहल, बड़े, सूचीबद्ध व्यवसायों के लिए एक अनिवार्य प्रकटीकरण ढांचा है जिसमें मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करने और पर्यावरण की रक्षा करने के सिद्धांत शामिल हैं।

बिहारः सीवान में बारिश के बीच ढहे 2 पुल, 15 दिन में सामने आई 7वीं घटना

उत्तरप्रदेश (एजेंसी)। बिहार में एक बार फिर से भारी बारिश के बीच 2 पुलों के ढहने की घटना सामने आई है। पिछले 15 दिनों में राज्य में हुई यह सातवीं घटना है। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। लगभग 35 साल पुराने दोनों पुल जिले के देवरिया ब्लॉक में स्थित हैं। इसके बाद से आवाजाही काफी प्रभावित हुई है। दोनों पुलों में से एक का निर्माण 1998 में तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह की निधि से 6 लाख रुपये में हुआ था, जबकि दूसरा पुल 2004 में 10 लाख रुपए की लागत से बना था। इसके बाद से ही दोनों पुलो की मुरम्मत नहीं की गई। इससे पहले मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जैसे जिलों में इसी तरह की घटनाएं सामने आई। इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद बिहार सरकार ने जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

हेमंत सोरेन फिर झारखंड के सीएम बनेंगे

रांची (एजेंसी)। हेमंत सोरेन फिर झारखंड के सीएम होंगे। आज ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज शाम साढ़े 7 बजे हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन राज्यपाल से मिलने जाएंगे। मुख्यमंत्री चंपाई इस्तीफा सौंपेंगे और हेमंत शपथ ग्रहण के लिए समय मांगेंगे। राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन अभी चेन्नई में हैं। वे आज शाम तक रांची लौटेंगे। इसके बाद वे सीधे राजभवन जाएंगे। इससे पहले रांची में सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। सभी विधायकों को सीएम हाउस में ही रहने को कहा गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 दिन पहले जेल से रिहा हुए हैं। उनकी रिहाई के साथ ही झारखंड की राजनीति गरमा गई है। सीएम हाउस पर आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। बैठक में जेएमएम-कांग्रेस और राजद के विधायक और मंत्री शामिल हुए।

भ्रष्टाचार केस में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। शराब नीति घोटाले में सीबीआई की तरफ से दर्ज कराए गए भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जुलाई को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। केजरीवाल शराब नीति से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ में बंद थे। वहीं केजरीवाल ने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में जस्टिस नीना बंसल ने मंगलवार (2 जुलाई) को सुनवाई की और सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। इधर शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार को ही दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल की कस्टडी 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल के वकील रजत भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला के सामने उनकी जमानत की याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए रखा। रजत भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को बिना सही न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए हिरासत में ले लिया गया था। वकील ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की मांग की।

हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक कंचन तनवे पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना

जबलपुर (एजेंसी)। खंडवा से भाजपा विधायक कंचन तनवे पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने एक सप्ताह के भीतर जुर्माना राशि हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें की यह पूरा मामला कांग्रेस के टिकट पर पराजित प्रत्याशी कुंदन मालवीय की चुनाव याचिका से संबंधित है। मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और यहां पर भाजपा विधायक को जबलपुर हाईकोर्ट में आना था। लेकिन वह नहीं पहुंची, जिसके बाद उनके ऊपर यह जुर्माना लगाया गया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कंचन तनवे ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और वह चुनाव जीत गई थीं। भाजपा प्रत्याशी कंचन ने रिटर्निंग ऑफिसर को जो जाति प्रमाण पत्र दिया था उसमें उन्होंने अपने पति मुकेश तनवे का नाम पिता की जगह पर लिख दिया जो मान्य नहीं होता।

डीसीडब्ल्यू के सदस्यों का स्वाति मालिवाल को पत्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की सदस्य किरण नेगी और फ़िरदोस खान ने स्वाति मालीवाल को एक कठोर पत्र लिखा है। इस पत्र में मालीवाल पर आरोप लगाया गया है कि वह 700 से अधिक महिलाओं के संघर्षों का उपयोग अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए कर रही हैं। नेगी और फ़िरदोस का यह पत्र मालीवाल को उनकी दिल्ली से राज्यसभा सदस्य की हैसियत से संबोधित करते हुए हाल ही में मालीवाल द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती देता है। कथित तौर पर, मालीवाल ने सार्वजनिक रूप से निर्वाचित सरकार की आलोचना की थी कि उसने डीसीडब्ल्यू को आवश्यक धनराशि जारी करने में विफलता दिखाई है, जिससे आयोग की वर्तमान चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।नेगी और फ़िरदोस इन दावों का जोरदार खंडन करते हैं और कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 2015 से डीसीडब्ल्यू के बजट को काफी बढ़ा दिया है। वे बताते हैं कि बजट केवल दो वर्षों में 5 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गया, जिससे संचालन का विस्तार हुआ, जिसमें 181 महिला हेल्पलाइन, रेप क्राइसिस सेल और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जो शहर में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से हैं। पत्र में मालीवाल के 181 महिला हेल्पलाइन बंद होने और डीसीडब्ल्यू को धनराशि रोकने के दावों का भी खंडन किया गया है। नेगी का आरोप है कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने नवंबर 2023 से डीसीडब्ल्यू को धनराशि रोकी है, बावजूद इसके कि कोर्ट ने निर्देश दिए थे।

मणिपुर में स्कूल-सरकारी दफ्तर बंद,असम में बाढ़ से तीन की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। मानसून ने तय समय से 6 दिन (2 जुलाई) पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया है। देशभर के तकरीबन सभी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। नॉर्थ-ईस्ट में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। मणिपुर और असम में बाढ़ आ गई है। मणिपुर सरकार ने बुधवार (3 जुलाई) को राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा की है, जबकि स्कूल आज और कल यानी 4 जुलाई तक बंद रहेंगे। मंगलवार (2 जुलाई) को सेनापति नदी में गिरे 25 साल एक व्यक्ति का शव निकाला गया। भारत-म्यांमार सड़क के 3 किमी से अधिक हिस्से में भी बाढ़ आ गई है। 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम में भी तीन लोगों की बाढ़ से जान चली गई। इससे राज्य में इस साल बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। राज्य के 23 जिलों में 11.3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सोमवार तक 19 जिलों में 6.44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित थे। गुजरात के जूनागढ़ में सड़कें बारिश के पानी में डूब गई हैं। इसकी वजह से 30 गांवों का संपर्क कट गया है। वंथली में सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक रिकॉर्ड 361 मिमी बारिश हुई। सौराष्ट्र और दक्षिणी क्षेत्र में 200 मिमी से ज्यादा बारिश हुई। अहमदाबाद में दो मंजिला बिल्डिंग की सीढ़ियों का एक हिस्सा ढह गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के जरिए बिल्डिंग में फंसे 16 लोगों को निकाला।

राज्यसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, सभापति धनखड़ ने की घोषणा

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा की बैठक को बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। उच्च सदन में राष्ट्रगीत की धुन बजाए जाने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के 264वें सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। वर्तमान सत्र में 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। उसी दिन उच्च सदन के पटल पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति रखी गई। उसी रोज प्रधानमंत्री ने अपनी नयी मंत्रिपरिषद का परिचय उच्च सदन में करवाया। उच्च सदन में 28 जून को भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश कर चर्चा की शुरूआत की थी। इसके बाद उच्च सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर 3 जुलाई तक चर्चा चली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उच्च सदन में इस चर्चा का करीब 2 घंटे तक जवाब दिया।

मणिपुर पर प्रधानमंत्री का बयान आश्चर्यजनक, स्थिति सामान्य नहीं है-कांग्रेस

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा हैरान करने वाला है कि मणिपुर में स्थिति सामान्य है क्योंकि वास्तविकता यह है कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी मणिपुर का कोई उल्लेख नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर स्थिति को सामान्य करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने सभी से राजनीति से ऊपर उठकर वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग की अपील की और साथ ही 'आग में घी डालने वालों को आगाह भी किया कि वे ऐसी हरकतें बंद करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मणिपुर के अधिकतर हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और दूसरे संस्थान खुल रहे हैं। इसी को लेकर भड़के पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है।रमेश ने 'एक्स पर पोस्ट किया, ''इस मुद्दे पर महीनों की चुप्पी के बाद आज राज्यसभा में ''नॉन-बॉयोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने आश्चर्यजनक दावा किया कि मणिपुर में स्थिति सामान्य है।

हाथरस भगदड़ में 122 मौतें, योगी बोले-यह साजिश जैसा

उत्तरप्रदेश (एजेंसी)। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हुई है। 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रातभर शवों का पोस्टमॉर्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर-उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौत की पुष्टि की है। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। बुधवार सुबह साढ़े 11 बजे सीएम योगी भी हाथरस पहुंचे। जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। घटनास्थल गए। अफसरों से पूरे हादसे की जानकारी ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- यह हादसा साजिश जैसा है। लोग मरते गए। सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने न तो प्रशासन को सूचना दी और न ही मदद की। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया।

हिंसा और नफ़रत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते-राहुल गांधी

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि ''हिंसा और नफ़रत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। उन्होंने गुजरात में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर पथराव किए जाने की निंदा करते हुए यह टिप्पणी की। राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर लोकसभा में की गई 'हिंदू विरोधी% टिप्पणियों के खिलाफ मंगलवार को अहमदाबाद में गुजरात प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के समक्ष आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी और सत्तारूढ़ भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसके प्रदेश कार्यालय पर पथराव किया। राहुल गांधी ने 'एक्स पर पोस्ट किया, ''गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफ़रत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते।

प्रधानमंत्री ने सदन में गलतबयानी की, झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है-खरगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए गलतबयानी की जिसके विरोध में विपक्ष को सदन से वाकआउट करना पड़ा। उन्होंने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि झूठ बोलना और लोगों को भ्रमित करना प्रधानमंत्री मोदी की आदत बन गई है। खरगे ने जब संवाददाताताओं को संबोधित किया तो उनके साथ कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और 'इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों के नेता भी थे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया, ''हम सबने इसलिए वाकआउट किया क्योंकि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पर जवाब देते हुए कुछ गलत बातें सदन में रखीं। झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना उनकी आदत है। उनका कहना था, ''मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि संविधान आपने नहीं बनाया, संविधान के आप लोग विरोधी थे। मैं यह बात सदन में उनके सामने रखना चाहता था। उन्होंने दावा किया, '' राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुखपत्र 'ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में 30 नवंबर, 1950 में लिखा गया था कि भारत के इस नए संविधान में सबसे बुरी बात है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है खरगे ने यह दावा भी किया कि जनसंघ और उससे जुड़े संगठनों ने संविधान का विरोध किया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबासाहेब भीमराम आंबेडकर के पुतले जलाए थे।

हार्दिक पंड्या ने वानिंदु हसरंगा से छीनी बादशाहत, भारतीय खिलाड़ी बना नंबर 1 ऑलराउंडर

नई दिल्ली (एजेंसी)। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को बड़ा फायदा हुआ है। दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से अहम योगदान निभाने वाले पंड्या ने वानिंदु हसरंगा को पछाड़ दिया है। जिसके बाद आईसीसी टी20 रैंकिंग में हार्दिक पंड्या दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। ये पहली बार है जब हार्दिक पंड्या पहली बार आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किए हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की तरफ से हार्दिक पंड्या ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया। साथ ही उन्होंने आखिरी ओवर में 2 विकेट लिए और भारत को ये जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक पंड्या को आईसीसी से खास तोहफा मिला। आईसीसी टी20आई ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पंड्या ने पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के नंबर-1 का टैक छीन लिया। इसके अलावा टी20आई ऑलराउंडर रैंकिंग में मार्कस स्टोइनिस, सिकंदर रजा, शाकिब अल हसन और लियाम लिविंगस्टन को एक-एक स्थान का फायदा हुआ।

टी20 वर्ल्ड कप में हार के बाद डेविड मिलर के संन्यास लेने की अफवाहें तेज

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारत के हाथों साउथ अफ्रीका की हार के बाद घातक बल्लेबाज डेविड मिलर के संन्यास लने की अफवाहों ने जोर पकड़ा है। इस बीच खुद स्टार बल्लेबाज ने इन चर्चाओं पर बयान दिया है। पहली बार टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका को करीबी मैच में 7 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

इस बीच, सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स में अक्रामक बल्लेबाज डेविड मिलर के टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने का दावा किया गया। डेविड मिलर ने खुद सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर करते हुए अफवाहों पर विराट लगा दिया है। मिलर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि, कुछ रिपोर्ट्स के विपरीत, मैंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है।

मैं प्रोटियाज के लिए खेलने के लिए उपलब्ध रहूंगा। सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। साउथ अफ्रीका के लिए मैच के आखिरी ओवर तक डटे रहे मिलर को हार के बाद बेहद निराश हुई थी, जिसे उन्होंने खुद जाहिर भी किया था। मिलर का कहना था कि ये निगलना काफी कठिन है।

भारतीय क्रिकेट टीम की रवानगी में विलंब

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कैरेबियाई द्वीप से रवानगी में देरी हो गई है क्योंकि चार्टर विमान अब तक यहां नहीं पहुंचा है। एयर इंडिया का विशेष चार्टर विमान जिसका नाम एआईसी24डब्ल्यूसी (एयर इंडिया चैंपियंस 24 विश्व कप) है, भारतीय टीम, उसके सहयोगी स्टाफ, खिलाड़ियों के परिवार और कुछ भारतीय क्रिकेट बोर्ड(बीसीसीआई) के अधिकारियों और भारतीय मीडिया को वापस लाने के लिए तैयार है जो पिछले तीन दिनों से तूफान बेरिल के कारण यहां फंसे हुए हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने शनिवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर सात रन की रोमांचक जीत हासिल कर खिताब जीता। दो जुलाई को अमेरिका के न्यू जर्सी से उड़ान भरने वाले विमान के स्थानीय समयानुसार रात दो बजे बारबडोस पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम के अनुसार विमान के अब बारबडोस से सुबह साढ़े चार बजे (स्थानीय समय) उड़ान भरने की उम्मीद है। दिल्ली पहुंचने में 16 घंटे का समय लगेगा जहां टीम गुरुवार को सुबह छह बजे (भारतीय समयानुसार) उतरेगी, बशर्ते टीम की रवानगी में और देरी नहीं हो।यहां ग्रांटली एडम्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार से परिचालन फिर से शुरू हो गया। इससे पहले भारतीय टीम को दो जुलाई को स्थानीय समयानुसार शाम छह बजे रवाना होना था और बुधवार को शाम सात बजकर 45 मिनट (भारतीय समयानुसार) पर पहुंचना था। खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे लेकिन इस कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तूफान बेरिल अब श्रेणी पांच से नीचे आकर श्रेणी चार का तूफान बन गया है और जमैका की ओर बढ़ रहा है।

बारबाडोस से रवाना हुई टीम इंडिया, स्वेदश लौटकर जल्द पीएम मोदी से करेगी मुलाकात

नई दिल्ली (एजेंसी)। फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने अपने नाम किया। 29 जून को हुए इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। जिसकी बदौलत टीम ने 13 साल का लंबा इंतजार खत्म किया। वहीं गुरुवार 4 जुलाई की सुबह टीम इंडिया दिल्ली पहुंच जाएगी। जिसके बाद रोहित शर्मा की अगुवाई में पूरी भारतीय टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा। बता दें कि, बारबाडोस में तूफान के कारण वहां की सरकार ने सभी उड़ानों पर रोक लगा दिया था।

जिसके बाद पूरे बारबाडोस में लॉकडाउन की स्थिति हो गई और टीम इंडिया को भी होटल के अपने कमरों में बंद होना पड़ा। लेकिन अब टीम इंडिया इंतजार के बाद गुरुवार को सुबह 6.20 बजे दिल्ली पहुंचेगी। भारतीय टीम को इससे पहले 2 जुलाई को बारबाडोस से रवाना होना था लेकिन विमान में देर से उतरने के कारण टीम के लौटने में देरी हुई। देश लौटने के कुछ घंटों के भीरत खिलाड़ियों को पीएम मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों से पीएम मोदी सुबह 11 बजे नाश्ते पर मिलेंगे।

विजयी टीम के सम्मान में मुंबई में एक रोड-शो करने की भी योजना है। दिल्ली से टीम इस फ्लाइट से मुंबई भी पहुंचेगी। गौरतलब है कि, टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 30 जून को पीएम मोदी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से फोन पर बात की और जीत की बधाई भी दी। अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम रोहित शर्मा को उनकी कप्तानी के लिए बधाई दी और उनके टी20 करियर की सराहना भी की। पीएम मोदी ने फाइनल मुकाबले में विराट कोहली की पारी के लिए उनकी भी तारीफ की और साथ ही भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना भी की। 2007 टी20 चैंपियन टीम की तर्ज पर ही रोहित शर्मा की विजयी टीम गुरुवार शाम 4 बजे नरीमन पॉइंट में नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम तक एक खुली छत वाली बस में परेड करेगी।

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और पुलिस के बीच बुधवार शाम को बैठक हुई थी। इसके साथ ही बीसीसीआई सचिव जय शाह 125 करोड़ रुपये की पुस्कार राशि भी बांटेंगे। दरअसल, बोर्ड के एक सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि, खिलाड़ी थके हुए हैं। इसलिए ये तय किया गया कि एनसीपीए, नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक छोटी सी खुली छत वाली बस परेड निकाली जाएगी। जो महज 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद पुरस्कार वितरण होगा।

बारबाडोस से स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली इस दिन पहुंचेगी टीम इंडिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय टीम ने बीते कुछ दिनों से बारबाडोस में फंसी हुई थी। टीम वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया को तूफान के कारण बारबाडोस में ही रुकना पड़ा। वहीं पहले टीम इंडिया बुधवार की शाम को दिल्ली पहुंचना था लेकिन अब ये समय बदल गया है। जिस कारण अब टीम इंडिया बीसीसीआई की स्पेशल फ्लाइट से इस दिन दिल्ली पहुंचेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीम इंडिया को लाने वाली बीसीसीआई की स्पेशल फ्लाइट दिल्ली में लैंड होगी। ये फ्लाइट भारतीय समय के अनुसार कल यानी गुरुवार को सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

वॉन और फ्लिंटॉफ के बेटे अंडर-19 में इंग्लैंड के लिए एक साथ कर सकते हैं डेब्यू

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंग्लैंड के माइकल वॉन और एंड्रयू फ्लिंटॉफ की जोड़ी के अपने टेस्ट करियर को समाप्त करने के पंद्रह साल बाद उनके बेटों के श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों से आयु वर्ग स्तर पर पारंपरिक प्रारूप में अपनी यात्रा शुरू करने की उम्मीद है। पूर्व एशेज विजेता इंग्लैंड के कप्तान वॉन के बेटे आर्ची वॉन को मंगलवार को 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया जिसमें 16 वर्षीय रॉकी फ्लिंटॉफ भी शामिल हैं जिन्होंने पहले ही युवा एकदिवसीय मुकाबलों में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण कर लिया है। टीम में पारिवारिक संबंध साफ नजर आते हैं। इंग्लैंड के मौजूदा लेग स्पिनर रेहान के भाई फरहान अहमद और इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जो डेनली के 17 वर्षीय भतीजे जेडन डेनली को भी टीम में जगह मिली है। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज और ऑफ स्पिनर 18 वर्षीय आर्ची ने इस सत्र की शुरुआत में अपने पहले पेशेवर अनुबंध में समरसेट का प्रतिनिधित्व किया। वह 2020 से टॉनटन में काउंटी के अकादमी ढांचे का हिस्सा रहे हैं। आर्ची को हालांकि अब तक समरसेट की शीर्ष टीम से खेलने का मौका नहीं मिला है। पिछले हफ्ते आयु वर्ग स्तर पर उन्होंने इंग्लैंड अंडर-19 एकदिवसय टीम के खिलाफ अभ्यास मैच में यंग लायंस आमंत्रण एकादश के लिए 83 गेंदों में 85 रन बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दाएं हाथ के ऑलराउंडर रॉकी इंग्लैंड की टीम के लिए 106 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। वॉन और फ्लिंटॉफ ने 1999 से 2008 के बीच एक साथ 48 टेस्ट मैच खेले थे। इंग्लैंड अंडर-19 टीम आठ से 11 जुलाई तक वर्म्सले में और 16 से 19 जुलाई तक चेल्टेनहैम में दो टेस्ट मैचों में श्रीलंका अंडर-19 से भिड़ेगी। इंग्लैंड अंडर-19 टीम इस प्रकार है- हमजा शेख (कप्तान), फरहान अहमद, चार्ली ब्रैंड, जैक कार्नी, जेडन डेनली, रॉकी फ्लिंटॉफ, केश फोंसेका, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, एडी जैक, फ्रेडी मैककैन, हैरी मूर, नोआ थेन और आर्ची वॉन।

ओलंपिक 2036 की मेजबान का लक्ष्य, गुजरात के सीएम ने की फ्रांस के राजदूत से चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में फ्रांस के राजदूत डॉ थिएरी माथौ ने मंगलवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राज्य में ओलंपिक खेलों के आयोजन में इस यूरोपीय देश की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने के तरीकों पर चर्चा की। बता दें कि, भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने की योजना बना रहा है। फ्रांस इस साल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में ओलंपिक की मेजबानी करेगा। गुजरात सरकार की ओर से यहां जारी बयान के मुताबिक, सीएम पटेल ने राजदूत माथौ के साथ बैठक में भारत की बोली सफल होने पर 2036 में गुजरात में ओलंपिक खेलों के आयोजन में फ्रांस की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने पर चर्चा की। बयान के मुताबिक पटेल ने ओलंपिक की मेजबानी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं में फ्रांस की समझ और कौशल का इस्तेमाल करने में गुजरात की गहरी रुचि व्यक्ति की। बयान के अनुसार, सीएम ने ये भी जानना चाहा कि ये बुनियादी ढांचा आयोजन से परे दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे कर सकता है।

अफगानिस्तान की ओलंपिक फुटबॉल टीम में लियोनेल मेस्सी को जगह नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। लियोनेल मेस्सी इस महीने के अंत में पेरिस में शुरू होने वाले ओलंपिक में अर्जेन्टीना की फुटबॉल टीम का हिस्सा नहीं होंगे। कोच जेवियर माशेरानो ने मंगलवार को घोषित टीम में विश्व कप विजेता टीम के चार सदस्यों को जगह दी जिसमें स्ट्राइकर जूलियन अल्वारेज और डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी शामिल हैं। इस साल चोटों से जूझ रहे 37 वर्षीय मेस्सी अभी कोपा अमेरिका में अर्जेन्टीना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टीम का लक्ष्य 2021 में जीते गए महाद्वीपीय खिताब का बचाव करना है। अर्जेन्टीना ने 2021 में कोपा अमेरिका जीतने के बाद 2022 में विश्व कप भी जीता था।

मेस्सी ने अपने एकमात्र ओलंपिक अभियान में 2008 में बीजिंग में टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की थी। ओलंपिक पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर-23 टीम के लिए होता है लेकिन प्रत्येक टीम में तीन अधिक उम्र के खिलाड़ियों को खिलाने की अनुमति दी जाती है। वर्ष 2004 और 2008 में खिलाड़ी के तौर पर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले माशेरानो कोपा अमेरिका खत्म होने के बाद गोलकीपर गेरोनिमो रूली, ओटामेंडी और अल्वारेज को टीम में शामिल करेंगे।हाल ही में रिवर प्लेट से मैनचेस्टर सिटी में शामिल हुए मिडफील्डर क्लॉडियो एचेवेरी भी टीम में शामिल होंगे। अर्जेंटीना 24 जुलाई को मोरक्को के खिलाफ ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट के अपने पहले मैच से पूर्व फ्रांस में दो मैत्री मैच खेलेगा।

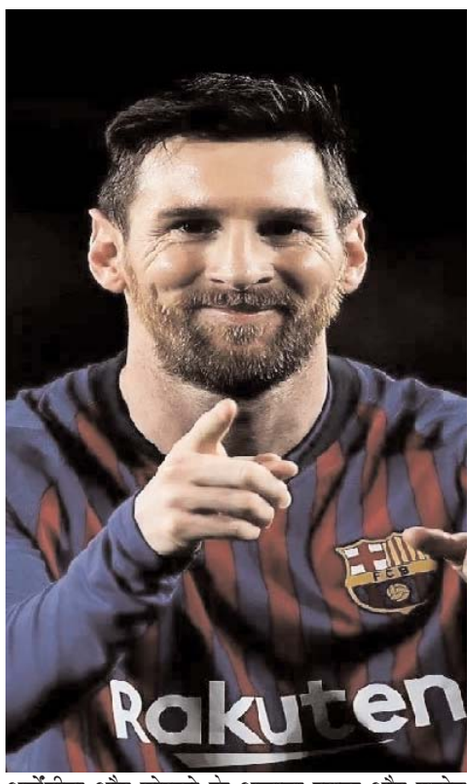

अर्जेंटीना और मोरक्को के अलावा इराक और यूक्रेन को ग्रुप बी में जगह मिली है।

कोलंबिया और ब्राजील ने 1-1 से ड्रॉ खेला, दोनों कोपा अमेरिका के क्वार्टर फाइनल में

सेंटा क्लारा। डेनियल मुनोज के पहले हाफ के इंजरी टाइम में दागे गोल की मदद से कोलंबिया ने ब्राजील को 1-1 से बराबरी पर रोककर कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप डी में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ब्राजील की टीम भी दूसरे स्थान पर रहते अंतिम आठ में जगह बनाने में सफल रही। राफिन्हा ने 12वें मिनट में ब्राजील को बढ़त दिलाई लेकिन मुनोज ने पहले हाफ के इंजरी टीम में गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया जिसके बाद दोनों ही टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। इस ड्रॉ से कोलंबिया ने अपने अजेय अभियान को 26 मैच तक पहुंचाया। कोलंबिया की टीम तीन मैच में दो जीत और एक ड्रॉ से सात अंक के साथ शीर्ष पर रही। ब्राजील ने एक जीत और दो ड्रॉ से पांच अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। पराग्वे (शून्य अंक) को 2-1 से हराने के बावजूद कोस्टा रिका (चार अंक) की टीम तीसरे स्थान पर रहते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गई। कोलंबिया शनिवार को क्वार्टर फाइनल में पनामा से भिड़ेगा जबकि ब्राजील का सामना इसी दिन उरूग्वे से होगा।

मोहम्मद रिजवान के लिए देश से बढ़कर है इस्लाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। हाल ही में संपन्न हुए टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम लीग स्टेज में ही बाहर हो गई थी। बाबर आजम की टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पाकिस्तानी टीम अपने पहले ही मैच में अपेक्षानुरुप प्रदर्शन नहीं कर पाई और सुपर ओवर में अमेरिका से हार गई। इसके बाद भारत के खिलाफ भी उन्हें हार झेलनी पड़ी। टीम की पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने काफी आलोचना की। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टीम की आलोचना सही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीम की आलोचना जायज है और हम इसके हकदार भी हैं। क्योंकि हमने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन इन सब के बीच रिजवान ने कुछ ऐसा भी कहा कि वो चर्चा का विषय बन गया। रिजवान ने कहा कि, मायूसी होगी, हम भी मायूस हैं। हमारी कौम भी हमसे मायूस होगी, क्योंकि जिस तरह से हमसे अपेक्षाएं थीं, क्योंकि अब अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं तो दर्द भी ज्यादा होता है। यही वह हमारी कौम है जो हमें इज्जत भी देती है और हमें बर्दाश्त भी करते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो बातें हमें कहीं जा रही हैं तो हम इसके हकदार हैं। रिजवान ने बात जारी करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग गलत कह रहे हैं। क्योंकि हमारे नतीजे ही बात करती है कि हमारी कौम हमसे मोहब्बत करे या हमें बर्दाश्त करे। मैं निजी रूप से कौम का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि जब हम पाकिस्तान लौटे तो हमें पता चला की हमारी कौम की हमारे प्रति अब भी पहले जैसे ही मोहब्बत है। वहीं एक सवाल के जवाब में रिजवान ने कहा कि मैं यह समझता हूं कि हर इंसान दो चीजों का ब्रांड एम्बेस्डर है। वह शफीर है, वह पहले इस्लाम का है, जब वह इस्लाम का शफीर होता है तो उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वह दुनिया में कहीं भी जाता है तो वह इस्लाम का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वह मुसलमान है तो...। दूसरा वह ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का। जब उससे नीचे (इस्लाम के बाद) बात आती है तो उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि वह कौन से सूबे से है। वह पाकिस्तान का है। लोग क्या कहते हैं हमें लोगों की परवाह नहीं है। रिजवान ने आगे कहा कि हम टी20 वर्ल्ड कप में अपने प्रदर्शन से निराश हैं। हमारी हार के पीछे कई कारण हैं। जब कोई टीम हारती है तो कोई ये नहीं कह सकता कि उसकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी अच्छी चल रही है। ऑपरेशन एक सामान्य बात है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो, ऑपरेशन जरूरी होता है। पीसीबी चेयरमैन एक मेहनती व्यक्ति हैं टीम में कौन रहेगा और कौन नहीं इसका फैसला चेयरमैन का अधिकार है।

प्राथमिकता से करे राजस्व प्रकरणों का निराकरण : कलेक्टर

अविवादित नामांतरण के 3 माह से ऊपर के प्रकरण नहीं रहे किसी कोर्ट में लंबित

मीडिया ऑडीटर, सतना निप्र। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने कोर्ट के आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करें। अविवादित नामांतरण, बंटवारा का कोई भी प्रकरण 3 माह से अधिक समय तक लंबित नहीं रहे। सभी एसडीएम अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का एक हफ्ते में निरीक्षण कर इस आशय का प्रमाण पत्र भी देंगे कि न्यायालयों में प्राप्त सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पर दर्ज कर लिये गये हैं। इस आशय के निर्देश गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े, एसडीएम एपी द्विवेदी, राहुल सिलाडिया, जीतेन्द्र वर्मा, सुधीर बेक, आरएन खरे, नीरज खरे, डिप्टी कलेक्टर एलआर जांगडे, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख एमएल तिवारी, जिला प्रबंधक योगेश तिवारी, लोक सेवा प्रबंधन ऋत्विराज मिश्रा भी उपस्थित थे।

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने राजस्व न्यायालयवार आरसीएमएस में दर्ज नामांतरण, बटवारा, सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा में कहा कि अगले हफ्ते तक 6 माह से अधिक अवधि से लंबित कोई प्रकरण राजस्व कोर्ट में नहीं मिलना चाहिए। नामांतरण के निराकरण की व्यवस्था देते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी कोर्ट में प्रत्येक माह की 1 से 15 तारीख तक दर्ज प्रकरणों का निराकरण अगले माह की 1 से 3 तारीख तक और 16 से 31 तारीख तक दर्ज प्रकरणों का निराकरण अगले माह की 16 से 18 तारीख तक हो जाना चाहिए। इस दौरान एक माह की अवधि में ईश्तहार प्रकाशन सहित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाए और तय समय सीमा में निराकरण हो। इस व्यवस्था की मानीटरिंग एसडीएम करेंगे और कमी पाए जाने पर सीधे राजस्व अधिकारियों पर बिना नोटिस कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में नागौद और रघुराजनगर को छोडकर अन्य तहसीलदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

आरसीएमएस पोर्टल पर राजस्व कोर्ट की समीक्षा में एसडीएम रामपुर बघेलान का निराकरण 31 प्रतिशत, मझगवां का 40 प्रतिशत, उचेहरा 46 प्रतिशत, रघुराजनगर 52 प्रतिशत, नागौद 63 प्रतिशत और नजूल का 65 प्रतिशत निराकरण पाया गया। इसी प्रकार तहसीलदार कोर्ट में बिरसिंहपुर का 14 प्रतिशत, रामपुर बघेलान 43 प्रतिशत, उचेहरा 46 प्रतिशत, कोठी 50 प्रतिशत, मझगवां 57 प्रतिशत, कोटर 58 प्रतिशत, रघुराजनगर 59 प्रतिशत और तहसील नागौद का 69 प्रतिशत निराकरण पाया गया। कलेक्टर ने नायब तहसीलदार कोर्टवार नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान 2 वर्ष से ऊपर के सभी प्रकरण निराकृत कर एक अगस्त तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिरसिंहपुर तहसील में राजस्व के हर आस्पेक्ट नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन में सबसे न्यून प्रगति पाये जाने पर तहसीलदार बिरसिंहपुर के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। बिरसिंहपुर तहसील कोर्ट में आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण 24 प्रतिशत, बंटवारा में 11 प्रतिशत और सीमांकन में 4 प्रतिशत ही निराकरण ही किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि अब प्रत्येक टीएल में आरसीएमएस में दर्ज नामांतरण, बटवारा, सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा होगी।

डी श्रेणी में हुई तहसील तो कटेगी एक हफ्ते की वेतन: कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन और आरसीएमएस पोर्टल की ग्रेडिंग में यदि कोई तहसील डी ग्रेड में पाई गई तो विभाग प्रमुख अधिकारियों की तरह तहसीलदार का भी एक हफ्ते का वेतन काटा जाएगा। सभी राजस्व कोर्ट 60 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर डी श्रेणी से बाहर आए। कलेक्टर ने कहा कि सतना जिला राजस्व प्रकरणों के निराकरण के मामले में हमेशा संभाग और राज्य स्तर पर अव्वल स्थान पर रहता था। इस बार की समीक्षा बैठक में 38 प्रतिशत निराकरण के साथ डी श्रेणी में रहा है। अविवादित नामांतरण में 70 प्रतिशत निराकरण से कम वाले नायब तहसीलदार, तहसीलदार को नोटिस जारी कर वेतन रोकने की चेतावनी भी दी। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक कोर्ट में हर आस्पेक्ट में 15 जुलाई तक 75 प्रतिशत निराकरण की पूर्ति की जाए। इसी माह की 19 जुलाई को राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर नामांकन, बटवारा, सीमांकन की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में 6 माह से अधिक के प्रकरण लंबित नहीं होने चाहिए। तहसीलदार बरौंधा को कलेक्टर ने सप्ताह के दो दिन बुधवार और शुक्रवार को तहसीलदार बरौंधा और शेष दिनों में मझगवां में कोर्ट लगाने के निर्देश दिए।

बारिश के मौसम में अलर्ट रहे राजस्व अधिकारी : कलेक्टर

मीडिया ऑडीटर, सतना निप्र। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि चालू वर्षा काल में अच्छे मानसून और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। बारिश के मौसम में सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहें। नदी-नालों में उफान आने पर पानी भरने वाले और निचले स्थानों को चिन्हित कर व्यवस्थाएं कर लें। बरसात के मौसम में बिजली गिरने की घटनायें भी हो रही है। बिजली गिरने से हुई जन-पशु हानि के लिए तत्काल राहत प्रकरण बनाएं और आर्थिक सहायता प्रदान करें। सड़कों और नदी-नाले के रपटों पर पानी आने पर आवागमन तत्काल प्रतिबंध कराये और बांध के जल स्तर पर नजर रखें।

कलेक्टर ने कहा कि कोटर को छोड़कर सभी तहसील मुख्यालय में वर्षा मापी यंत्र लगे हैं। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि दैनिक वर्षा की माप की जाकर प्रात: 8 बजे तक जानकारी एस एलआर को दी जाए। कलेक्टर ने बताया कि राज्य स्तर पर डिजास्टर वार्निंग एंड रिस्पांस सिस्टम तैयार हो रहा है। इसके माध्यम से जिले के विभिन्न स्थानों पर प्राकृतिक आपदा संबंधी पूर्व सूचना मिल सकेगी।

नि:शुल्क कोचिंग के लिये पंजीयन 4 एवं 5 जुलाई को

मीडिया ऑडीटर, सतना निप्र। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ''बेटी बचाओ-बेटी पढाओ'' योजना अंतर्गत 10 2 परीक्षा उत्तीर्ण युवतियों/बालिकाओं को जिला स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 30-40 युवतियों/बालिकाओं के नवीन बैच का संचालन किया जा रहा है। जिसमें 18 से 28 वर्ष (आरक्षित वर्ग 18 से 33 वर्ष) तक की बालिकाएँ शामिल हो सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सौरभ सिंह ने बताया कि शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाली युवतियों/महिलाओं को कुल 3 माह तक लिखित परीक्षा की तैयारी नि:शुल्क कराई जाएगी। नि:शुल्क कोचिंग में प्रवेश के लिए 4 एवं 5 जुलाई को युवतियों/बालिकाओं का पंजीयन जिला बाल संरक्षण इकाई कन्या धवारी स्कूल के पास सतना में प्रात: 11 बजे से सायं 4 बजे तक किया जायेगा।

किसान, गोबर और गौ-मूत्र से खाद बनाएँ

मीडिया ऑडीटर, सतना निप्र। किसान भाई सदियों से गोबर से खाद बनाता आया है। कृषि विभाग के अधिकारी प्राकृतिक संसाधनों से जैविक खाद का अपयोग करने की सलाह लगातार दे रहे है अब किसान जान गए है और अब कई किसानों ने गौ-मूत्र और गोबर, पत्तों से खाद बना कर खेतों में उपयोग किया जा सकता है। हम सभी को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभानी होगी। प्राकृतिक खेती हम सभी के लिये लाभदायक है।

मध्यप्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। कई किसानों ने अपने खेत में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की है। वे गोबर, गौ-मूत्र, मिट्टी, पत्ते, वनस्पति से जीवामृत बना रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों से खाद बनाने में लागत भी कम आती है और फसल में पैदावार भी अच्छी होती है। प्रदेश में प्राकृतिक उत्पाद की मांग बढ़ी है।

प्लेसमेंट कैम्पस ड्राइव 9 जुलाई को

मीडिया ऑडीटर, सतना निप्र। प्राचार्य शासकीय आईटीआई सतना द्वारा बताया गया कि पीथमपुर द्वारा अप्रेन्टिस शिप हेतु 10वीं एवं इंजीनियरिंग ट्रेड में शासकीय आईटीआई से एनसीवीटी/एससीवीटी में वर्ष 2022, 2023, 2024 में 60 प्रतिशत प्राप्त करने वाले पात्र उम्मीदवारों के लिए 9 जुलाई 2024 को प्रात: 10 बजे से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सतना में एक दिवसीय प्लेसमेन्ट/कैम्पस ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। कैम्पस ड्राइव में 18 से 25 वर्ष आयु तक के पुरूष बेरोजगार आवेदक जो निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं। वे अपने साथ 3 प्रति में बायोडाटा, आधारकार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट फोटो एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते है।

मैहर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थित में दिया गया नए कानून का प्रशिक्षण

मीडिया ऑडीटर, सतना निप्र। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मैहर कलेक्टर रानी बाटड एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल की उपस्थिति में अति. जिला अभियोजन अधिकारी रीवा आदर्श सिंह सोलंकी द्वारा जिले के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं विभागीय अधिकारियों को 1 जुलाई से लागू नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक मुकेश वैश्य, एसडीएम मैहर विकास सिंह, एसडीएम अमरपाटन आरती यादव, एसडीएम रामनगर डॉ. आरती सिंह, लोक अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय, निरीक्षक अंजु पटेल, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, रामदेव साकेत एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर बाटड ने कहा कि भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में बदल गया है। अब न्याय संहिता पीड़ित केंद्रित हो गई है। अब जनता को जल्द न्याय मिलेगा। न्याय जल्द मिले इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब पीड़ित स्वयं अपनी तरफसे वकील भी ले जा सकता है। किसी भी केस में पीड़ित को सुनना अब बहुत जरूरी है। बिना सुने किसी भी केस की वापसी नहीं होगी। नवीन धाराओं में जुर्माने के साथ-साथ सजा की अवधि भी बढ़ाई गई है। कई नई धारा जोड़ी गई है और कुछ हटाई गई है। जीरो एफ्आईआर और ई एफ्आईआर का प्रावधान किया गया है। पहले 167 धारा हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर अब 170 कर दी गई है। सुरक्षा के साथ न्याय दिलाने पर ज्यादा फोकस किया गया है। आतंकवादी कृत्य को भी इसमें शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश में एक जुलाई से तीन नवीन कानून लागू किये गये। भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक जुलाई 2024 से प्रदेश में लागू कर दिया गया। नवीन कानूनों के संबंध में लोगों को जानकारी देने तथा जागरूक करने के उद्देश्य से जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

सतना मेडिकल कॉलेज को मिलेगा बजट

रामवन गमन पथ का होगा विकास, विंध्य एक्सप्रेस वे, पीएम श्री कॉलेज बनेगा

मीडिया ऑडीटर, सतना निप्र। आए दिन वेतन के लिए कर्मचारियों के आंदोलन की स्थिति का सामना कर रहे सतना मेडिकल कॉलेज की माली हालत सुधरेगी जबकि कॉलेज की शिक्षा के लिए महाविद्यालय की पुरानी चली आ रही मांग के बीच सतना को पीएम श्री कॉलेज की सौगात भी मिलेगी। इसके साथ ही 676 किमी लंबे विन्ध्य एक्सप्रेस वे का निर्माण भी किया जाएगा।

मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने रतलाम, दतिया, शिवपुरी के साथ सतना मेडिकल कॉलेज के लिए भी 631 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट में प्रावधानित की गई इस राशि मे से सतना के शासकीय मेडिकल कॉलेज के हिस्से में भी राशि आएगी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह राशि सतना मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल बनवाए जाने की आवश्यकता पूर्ति पर खर्च की जाएगी अथवा इस रकम से कॉलेज की प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य जरूरी खर्च किए जाएंगे।

रामवन गमन पथ पर ध्यान: प्रदेश सरकार ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के वन गमन पथ के विकास पर भी फोकस किया है। बजट में श्रीराम वन गमन पथ को विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। जिसके तहत उन स्थानों को चिन्हित और विकसित किया जाएगा जहां भगवान राम ने वनवास काल के दौरान समय व्यतीत किया था। भगवान श्रीराम ने वनवास काल मे सर्वाधिक साढ़े 11 साल का समय सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में व्यतीत किया था। इस अंचल में भगवान की स्मृतियां जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। उम्मीद है कि सरकार के इस प्रोजेक्ट से इन तमाम पौराणिक और धार्मिक महत्व की धरोहरों को संरक्षित किया जा सकेगा।

वित्त मंत्री ने प्रदेश के हर जिले में पीएम श्री कॉलेज खोले जाने की भी घोषणा की है जिसका फायदा सतना को भी निश्चित तौर पर मिलेगा। सतना जिला मुख्यालय में एक और शासकीय महाविद्यालय की आवश्यकता पिछले काफी समय से महसूस की जा रही है। पीएम श्री कॉलेज के जरिये छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब मैहर भी सतना से पृथक होकर अलग जिला बन चुका है लिहाजा एक पीएम श्री कॉलेज मैहर में भी बनेगा।

इसके अलावा सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत विन्ध्य के जिलों को 676 किमी लंबे विन्ध्य एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा।पुलिस विभाग में की जाने वाली भर्तियों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

राजस्व प्राप्तियों का जिले का लक्ष्य 26 करोड

मीडिया ऑडीटर, सतना निप्र। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में बताया कि इस वर्ष राज्य शासन द्वारा सतना जिले में राजस्व प्राप्तियों का लक्ष्य 15 से बढ़ाकर 26 करोड रुपए निर्धारित किया है। पिछले वर्ष निर्धारित लक्ष्य 15 करोड़ के विरुद्ध 13 करोड़ की राजस्व की प्राप्तियां हुई थी। राजस्व अधिकारी राजस्व वसूली पर ध्यान देकर माहवार नियमित रूप से राजस्व वसूली करायें।

चित्रकूट अनुभाग बने पर बरौंधा को उसमे जोड़ना उचित नही : संजय सिंह

मीडिया ऑडीटर, चित्रकूट निप्र। धर्मनगरी चित्रकूट को अब चित्रकूट अनुभाग बनाया जा रहा है जहां मझगवां के अलावा एक एसडीएम चित्रकूट में बैठेंगे ऐसी व्यवस्था को लेकर बरौंधा क्षेत्र की की 25 पंचायतें और चित्रकूट की 5 पंचायते जोड़कर 111 गांवो की नई तहसील चित्रकूट और अनुभाग बनाया जा रहा है जिसको लेकर अब स्थानीय नेता एवं वार्ड क्रमांक 23 से जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह कछवाह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अनुभाग बनाए अच्छी बात पर बरौंधा क्षेत्र की पंचायतों को उसमे जोड़ना बिल्कुल सही नही है क्योंकि बरौंधा क्षेत्र के पाथरकछार से चित्रकूट की दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास है वही बरौंधा से लभगभ 70 किलोमीटर है अगर ऐसे में बरौंधा को चित्रकूट में जोड़ा जाएगा यहां के लोगो को अपने कार्यो के लिए बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी, यही नही यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जहां गरीब परिवार के लोग अपना गुजर बसर करते है जो इतनी यात्रा करने के लिए भी सक्षम नही है क्योंकि राजस्व के मामले सालों साल चलते है जिस कारण लोगो को काफी परेशानी होगी और बरौंधा क्षेत्र के लोगो मुझसे उस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य होने के नाते उन्होंने मांग रखी है कि बरौंधा क्षेत्र को चित्रकूट से न जोड़ा जाय, ऐसे में जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते सतना जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा से मांग करता हु की बरौंधा क्षेत्र को यथास्थित रखा जाय क्योकि चित्रकूट को अनुभाग बनाने के चक्कर मे बरौंधा क्षेत्र के लोगो के साथ इस प्रकार अन्याय बर्दास्त नही है, अगर अनुभाग बनाना है तो बिरसिंहपुर को बनाएं वह बड़ा क्षेत्र है उसमे जैतवारा को शामिल कर एक अनुभाग बनाया जा सकता है लेकिन बरौंधा को चित्रकूट में जोड़ना कतई न्योचित नही है मैं संजय सिंह कछवाह एवं बरौंधा क्षेत्र की समस्त जनता इस बरौंधा को चित्रकूट में जोड़ने का विरोध करते है।

लंबित शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में तत्परता के साथ करें

कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिये निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सतना निप्र। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को आयोजित समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर रानी बाटड ने सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई के लंबित प्रकरणों सहित विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि ऊर्जा विभाग की लंबित 2474 शिकायतों में 35 कम हुई है। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग की 19, राजस्व की 1214 शिकायतें हैं, जिसमे 288 शिकायतें एल-1 पर है। पीएचई विभाग की कुल शिकायते 950 तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की कुल शिकायतें 1031 है। कलेक्टर श्रीमती बाटड ने निर्देशित करते हुए कहा कि ऊर्जा, राजस्व, पीएचई और महिला बाल विकास लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए तत्परता से कार्य करें। उन्होंने इस सप्ताह शिकायतों के निराकरण में 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिन विभागों की शिकायते कम है, तो एल-1 पर आई शिकायतो को नजर अंदाज न करे। उन्होंने कम शिकायतो को भी गंभीरता से देखते हुए निराकरण कर बंद करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अमरपाटन आरती यादव, एसडीएम रामनगर डॉ आरती सिंह, डीपीओ राजेंद्र बांगरे, सीईओ प्रतिपाल बागरी, सीएमओ अमरपाटन सुषमा मिश्रा, पीआईयू मन्दाकनी गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

समय सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने जिले के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों व ग्राम पंचायत भवन के बाहर सूचना बोर्ड लगाने और उस पर सरपंच, सचिव और समिति का नाम, नम्बर तथा खुलने का समय अंकित करने के निर्देश दिए। सीएम राइस विद्यालय मैहर और अमरपाटन के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि विद्यालय प्रारंभ हो गए है। निर्माण एजेंसी द्वारा बताया कि 15 जून से पहले बिल्डिंग का कार्य पूर्ण कर विभाग के हैंडओवर कर दिया जाएगा मगर ऐसा नहीं किया गया। इस संबंध में डीईओ नीरव दीक्षित और पीआईयू को निर्माण कार्य की जांच करते हुए जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। अमरपाटन में निर्माण एजेंसी द्वारा विद्यालय की जमीन पर असीमित खोदाई किये जाने पर खनिज विभाग को निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया प्रकाशन रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय प्रभात बिहार कॉलोनी सतना से प्रकाशित, संपादक संदीप द्विवेदी आर.एन.आई नं.एमपीएचआईएन/2021/81683
प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9407132714, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार, सभी विवादो का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।